चिंतन

परवान नहीं चढ़ रहीं रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका को ही भारी पड़ रहा है। टैरिफ वार की सनक के चलते जहां अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, वहीं अमेरिकियों को महंगाई की आंच सहन करनी पड़ रही है। ब्याज के मुद्दे पर ट्रंप की अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व से ठनी हुई है, तो रूस व यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने के उनके वादे खोखले साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर दुनिया की नजरें थीं, लेकिन इस मुलाकात से कुछ निकला नहीं। रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका। बैठक से पहले ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल अकाउंट पर बड़े दावे कर रहे थे कि वह यूक्रेन में युद्धविराम देखना चाहते हैं और यदि इस पर सहमति नहीं बनी तो वह खुश नहीं होंगे, लेकिन मंझे हुए नेता पुतिन के साथ उनकी दाल नहीं गली। यूक्रेन का भूगोल बदलने की रूसी मंशा किसी भी नतीजे पर पहुंचने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इस बैठक को लेकर यूक्रेन पहले से सशंकित था और चाहता था कि उनकी उपस्थिति के बिना रूस के साथ कोई निर्णायक बात न हो और ट्रंप कुछ भी एकतरफा वादा न करें। ऐसे में ट्रंप व पुतिन की अलास्का वार्ता के बेनतीजा रहने से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राहत की सांस ली होगी। इस वार्ता से पहले जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना रूस के साथ कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए व जमीन अदला-बदली को यूक्रेन नहीं मानेगा। यूरोपीय संघ भी यूक्रेन के साथ है और वह भी चाहता था कि वार्ता सभी संबंधित पक्ष की मौजूदगी में हो। आज सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक करेंगे, इसमें युद्ध विराम के लिए रूपरेखा पर बात होगी। ट्रंप पुतिन की मंशा को केंद्र में रखकर अगर यूक्रेन व ईयू से बात करेंगे, तो इसमें भी कुछ नतीजा की उम्मीद नहीं है। रूस यूक्रेन के चार सीमाई क्षेत्र पर कब्जे को लेकर अड़िग है, यूक्रेन किसी भी स्थिति में अपना क्षेत्र गंवाना नहीं चाहता है। यूक्रेन को ईयू का शह भी प्राप्त है। अमेरिका के पास भी रूस व यूक्रेन दोनों को मान्य कोई योजना नहीं है, यह अब तक साफ हो चुका है। ट्रंप दबाव डाल कर युद्ध विराम चाहते हैं, पर यह कोई कूटनीतिक तरीका नहीं है। ट्रंप का रूस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ दांव भी काम करता नहीं दिख रहा है, इसलिए यूक्रेन व ईयू के साथ ट्रंप की बैठक में किसी बिंदु पर सहमति बनने की संभावना कम प्रतीत हो रही है। हालांकि इस बैठक के बाद ट्रंप पुतिन के साथ मास्को में बैठक कर सकते हैं, लेकिन यह इस वार्ता पर निर्भर करेगा। बेशक ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन व रूस के बीच जारी जंग खत्म हो जाए, पर इसके लिए वार्ता ही काफी नहीं है। अमेरिका व ईयू का जब तक रणनीतिक रवैया नहीं बदलेगा, तब तक सुलह की उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले अमेरिका और ईयू यूक्रेन को सामरिक व आर्थिक मदद देना बंद करें, यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने का भूत छोड़ दें और यूक्रेन के कंधे से रूस के विनाश का स्वप्न देखना छोड़ दें। यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ देश है, इसलिए उसकी आत्मा कभी भी यूएस व ईयू के साथ घुलमिल नहीं सकेगी। यह बात यूक्रेन को भी समझनी चाहिए और यूएस-ईयू को भी। भारत ने हमेशा शांति की पक्षधरता की है और यूक्रेन व रूस के बीच वार्ता के जरिये जंग खत्म करने की चाहत प्रकट की है। पीएम नरेन्द्र मोदी अभी पुतिन से मिले हैं और जेलेंस्की से फोन पर बात की है। इन प्रयासों से जंग खत्म होने का रास्ता निकलना चाहिए।

एनसीईआरटी
प्रमोद भार्गव

भारत के विभाजन के दोषी कौन

एनसीईआरटी द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी एक विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह भी उल्लेख है कि विभाजन के बाद कश्मीर नई समस्या के रूप में पेश आया। इसने देश की विदेश नीति के लिए चुनौती बनाए रखी। नतीजतन कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। भारत का विभाजन बनाम विचारों के कारण हुआ। भारतीय मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज से संबंधित हैं। अतएव एक साथ नहीं रह सकते।' एनसीईआरटी के विशेष पाठ में 'विभाजन के अपराधी' शीर्षक वाले खंड में कहा है कि 'अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। किंतु यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए तीन कारण जिम्मेदार थे, एक जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की। दूसरे कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इस पर अमल किया। माउंटबेटन एक बड़ी भूल के दोषी साबित हुए।'

एनसीईआरटी ने उक्त दो पार्ट छापे हैं। इनमें छठी कक्षा से आठवीं के लिए और नौवीं कक्षा से बारहवीं के लिए एक-एक पाठ हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी में पूरक पाठ हैं, नियमित पाठ्य पुस्तकों में नहीं हैं। इसलिए इनका प्रयोग परियोजनाओं, पोस्टरों और वाद-विवादों के माध्यम से किया जाना है। ये दोनों पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में दिए गए संदेश के साथ शुरू होते हैं, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साफ है, ये पाठ पूरे देश में वाद-विवाद का ऐसा हिस्सा बनें, जिससे लोग जान सकें कि वास्तव में विभाजन के अपराधी कौन हैं। केंद्र सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होती दिख रही है। दरअसल स्वतंत्रता संघर्ष के बीच महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास से कहा था कि 'अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जब तक मैं जीता हूं, मैं कभी भी हिन्दुस्तान का बंटवारा स्वीकार नहीं करूंगा और जहां तक मेरा वश चलेगा, कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं करने दूंगा।' अलबत्ता ऐसा एकाएक क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे के समर्थन में खड़े होना पड़ गया। लार्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात में ही गांधी उनके वाग्जाल की गिरफ्त में ऐसे आए कि उनकी प्राण जाए, पर वचन न जाए, की वचनबद्धता भंग हो गई। कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद के आगे घुटने टेकती चली गई। नतीजतन भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश संसद में मोहर लगा दी गई। ब्रितानी हुकूमत में औपनिवेशिक दासता झेल रहे अखंड भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र देश बनाकर पृथक-पृथक सत्ता का हस्तांतरण करने का निर्णय ले लिया। संपूर्ण सत्ता सौंपने का दिन 14 अगस्त 1947 निश्चित किया। यह दिन भी एक तरह से दोनों देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को चिढ़ाने की दृष्टि से मुकर्रर किया

गया, क्योंकि इसी दिनांक को जापान मित्र देशों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने की दृष्टि से बंगाल विभाजन एक ऐसा षड्यंत्रकारी घटनाक्रम रहा जो भारत विभाजन की नींव डाल गया। इस बंटवारे के फलस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी उग्र जनभावना फूटी की बंग-भंग विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया।

दरअसल जब गोरी पलटन ने समूचे भारत को अपनी अधीनता में ले लिया, तब क्रांतिकारी सेनानियों और बिट्रोहियों के साथ कठोरता बरतने के लिए 30 सितंबर 1898 को भारत की धरती पर वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पैर पड़े। कर्जन को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ले रहे क्रांतिकारियों के दमन के लिए भेजा गया था। इस संग्राम पर नियंत्रण के बाद फिरंगी इस बात को लेकर चिंतित व सतर्क थे कि कहीं इसकी राख में दबी चिंगारी फिर न सुलग पड़े। क्योंकि अंग्रेज भली भांति जान गए थे कि 1857 का सिलसिला टूटा नहीं है। अंग्रेजों को यह भी शंका थी कि कांग्रेस इस असंतोष को पनपने के लिए खाद-पानी देने का काम कर रही है। कर्जन ने अंग्रेजी सत्ता के संरक्षक बने मुखबिरों से ज्ञात कर लिया कि इस असंतोष को सुलगाए रखने का काम बंगाल से हो रहा है। वाकई स्वतंत्रता की यह चेतना बंगाल के जनमानस में एक बेचैनी बनकर तैर रही थी। यह बेचैनी 1857 के संग्राम जैसे रूप में फूटे, इससे पहले कर्जन ने कूटिल क्रूरता के साथ 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। जबकि इस बंग-भंग का विरोध हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किया था। इस बंटवारे का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल इलाके को बंगाल कहा गया। अर्थात जिस भूखंड पर हिंदू-मुस्लिम संयुक्त भारतीय नागरिक के रूप में रहते चले आ रहे थे, उनका मानसिक रूप से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। इस विभाजन से सांप्रदायिक भावना की एक तरह से बुनियाद डाल दी गई, वहीं दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे भारत में अंग्रेजी के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया। लेकिन कर्जन ने इसे कूटिल चतुराई से मुस्लिम लीग की स्थापना में बदल दिया। यही नहीं, कर्जन ने अपने वाकचातुर्य से ढाका के नवाब सलीमुल्ला को बंगाल विभाजन का समर्थन और अचानक उदय हुए स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए राजी कर लिया। सलीमुल्ला कर्जन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सक्रिय होकर कुछ नवाबों को बरगलाकर दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग संगठन खड़ा कर दिया। स्वदेशी आंदोलन को विफल करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने सलीमुल्ला के साथ मिलकर हिंदू-मुस्लिमों के बीच संप्रदाय के आधार पर दंगे भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। यहीं से हिंदुओं की हत्या करने और उनकी संपत्ति लूटने व हड़पने का सिलसिला शुरू हो गया। नतीजतन मुस्लिम नेता पूरी ताकत से बंटवार के समर्थन में आ खड़े हुए। लॉर्ड माउंटबेटन इतना चतुर निकला कि उसने विभाजन के लिए जिन्ना, नेहरू, पटेल और यहां तक की गांधी को भी मना लिया। भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यही नहीं पंजाब और बंगाल को भी कपड़े की तरह दो टुकड़ों में चीर दिया गया, जिससे भारत हमेशा गृह कलह की आंच से सुलगता रहे। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझ कर 652 भारतीय रियासतों की प्रभुसत्ता उन्हें वापस सौंप दी। उन्हें भारत या पाकिस्तान मिल जाने की छूट तो थी ही, स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की छूट भी दे दी गई थी। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ विभाजन तो आधा सच है, पूरा सच तो देश के 652 टुकड़े कर देने का बन गया था। जिसे पटेल ने संभाला और रियासतों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो पाया। यह ऐतिहासिक सत्य है, जो स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास पुस्तकों में पूर्व से ही दर्ज है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

> एनसीईआरटी द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी एक विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है। यह भी उल्लेख है कि विभाजन के बाद कश्मीर नई समस्या के रूप में पेश आया। इसने देश की विदेश नीति के लिए चुनौती बनाए रखी। नतीजतन कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ विभाजन तो आधा सच है, पूरा सच तो देश के 652 टुकड़े कर देने का बन गया था, जिसे पटेल ने संभाला और रियासतों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो पाया।

आर्थिकी
सतीश सिंह

मजबूत होती बैंकिंग इंडस्ट्री

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने 15 अगस्त को भारत के 10 बैंकों की रेटिंग का उन्नयन किया, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक,एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक शामिल हैं। इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस की रेटिंग का भी उन्नयन किया गया। रेटिंग उन्नयन यह दर्शाता है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों कीवित्तीयस्थितिबेहतरहुईहैऔरये बेहतरी के सभी पैमानों पर बेहतर कार्य कर रहे हैं। इससे बैंकों के ब्रांड इमेज में भी बेहतरी आयेगी, जिसका फायदा लंबी अवधि में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मिलेगा। गौरतलब है कि 14 अगस्त को वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में 18 सालों के बाद उन्नयन किया था। नई रेटिंग "बीबीबी"दर्शाता है कि देश के पास अपने कर्ज दायित्वों को आसानी से पूरा करने की क्षमता में सुधार हुआ है। अब भारत की रेटिंग मैक्सिको, इंडोनेशिया और ग्रीस के समान स्तर पर आ गई है। एजेंसी ने भारत की आर्थिक मजबूती, बेहतर राजकोषीय नीतियों और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को इस उन्नयन का आधार बताया है।वैसे,भारत की मजबूत मौद्रिक नीतियां और नियंत्रित मुद्रास्फीति ने भी इस उन्नयन में अहम भूमिका निभाई है। कुछ दिनों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 27 अगस्त से 50 प्रतिशत टैरिफ आरोपित करने की घोषणा की थी साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को मृतप्राय कहा था। बहरहाल, रेटिंग में उन्नयन से ट्रंप के बयान को करारा जवाब मिला है। पुनश्चः एजेंसी के अनुसार, ट्रंप के बयान से भारतीय अर्थव्यवस्था को महज अल्प अवधि के लिए नुकसान हो सकता है, वह भी आर्शिक स्तर पर।लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। इतना ही नहीं,इस रेटिंग उन्नयन से देसी और अंतरराष्ट्रीय निवेशक दोनों भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे का भी अनुमान है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत बने रहने से बैंकिंग इंडस्ट्री को लाभ हो रहा है।सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की समीचीन मौद्रिक नीति से महंगाई नियंत्रण में है और बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा हो रहा है।साथ ही, इससे निवेश, खर्च और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। गुलाबी अर्थव्यवस्था से भारतीय बैंकों को विदेश में अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल रही है।बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में कमी आ रही है और उनके कारोबार और मुनाफे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साथ ही, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बने रहने में मदद मिल रही है।इसतरह,बैंक और अर्थव्यवस्था के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है और दोनों के मजबूत रहने से देश के विकास को रफ्तार मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1.78 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया था,जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 26 प्रतिशतअधिक है।इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में सभी 12 सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा था।इसतरह, बैंकों के मुनाफे में विगत वित्त वर्ष में लगभग 37,100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई.इस रिकॉर्ड लाभ में सबसे बड़ा योगदान देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का रहा, जिसने अकेले 70,901 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया, जो बीते वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है और कुल सरकारी बैंकों के मुनाफे के 40 प्रतिशत से अधिक है।वहीं,प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ पंजाब नेशनल बैंक ने अर्जित किया, जो 102 प्रतिशत है और यह राशि में 16,630 करोड़ रुपए है।इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो राशि में 1,016 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने 40 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक ने क्रमशः 36.1 प्रतिशत और 35.4 प्रतिशत की वृद्धि मुनाफे में दर्ज कीत्वह उपलब्धि इसलिएमहत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों को सामूहिक रूप से 85,390 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सार्वजनिक बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एनपीए की पहचान, समाधान, वसूली, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण और वित्तीय पारिस्थितिकी में सुधार करने की रणनीति अपनाई थी, जिसके तहत वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक सरकारी बैंकों में 3.10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया। सरकार ने बीते कुछ सालों में बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास में बड़े निवेश के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलत सोच का चश्मा जल्दी उतार देना चाहिए

संकलित
दर्शन

जब सोच निषेधात्मक या गलत होती है, तब वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी हो, उतार देना चाहिए। यूं विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, उतना ही स्वयं का भी करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। कहा गया है कि आपके विचार वहां तक हो जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। पर कमजोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वह सब विचारों का फल है। जो हम सोचते हैं, वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से स्वयं को। गलत सोच एवं अमैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वह पुनर्चिंतन करता है-क्या मिला मुझे आदर्शों पर चलकर? यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों के संक्रमण से हुई। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया सिमट जाती हैं। तब हमारी छोटी-सी सफलता आंकार बढ़ाने लगती है। थोड़ा-सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाता है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज्यादा सीखने नहीं देता। हमारा चिंतन गुणों की ओर केंद्रित रहना चाहिए।

अपनी गठरी टटोलें

संकलित
प्रेरणा

दो आदमी यात्रा पर निकले! दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य एक था तो दोनों यात्रा में साथ हो चले। सात दिन बाद दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा: भाई साहब! एक सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा: नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला: महोदय मैं एक नामी ठग हूँ परन्तु आप तो महाठग हैं। आप मेरे भी गुरू निकले। दूसरा यात्री बोला: कैसे? पहला यात्री: कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर सात दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता है आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है? बिल्कुल खाली हाथ हैं! दूसरा यात्री: मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी-सी रजत मुद्राएं भी है। पहला यात्री बोला: तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद यह मुझे मिले क्यों नहीं? दूसरा यात्री: मैं जब भी बाहर जाता, वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम सात दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे। अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी। तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहाँ से! ईश्वर नित नई खुशियाँ हमारी झोली में डालते हैं परन्तु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है, यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताकझांक बंद कर देगा उस क्षण खरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी गठरी टटोलें! जीवन में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है स्वयं को टटोले और जीवन-पथ पर आगे बढ़े सफलताएं आप की प्रतीक्षा में है।

अंतर्मन

आज की पाती

साइबर क्राइम के बढ़ते कदम रोकने होंगे

जिस गति से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, यह आम आदमी के लिए एक मुसीबत बन गई है और लुटेरों के लिए जैसे मनोरंजन और लॉटरी लगी है। हैरानी इस बात की है कि इस मर्ज की दवा किसी के पास नहीं। किसी को जब चाहे, अपराधी बंधक बना कर सब कुछ लूट लेते हैं और उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देश की बड़ी संख्या में लोग इस क्राइम के शिकार हो रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है और इससे आंख नहीं फेरी जा सकती। जहां डिजिटलाइजेशन के अनेक लाभ हैं, इससे कई गुणा हानियां भी है। द्वंद्व यह है कि इसे अपनाएं या नहीं? इस पर सभी को गंभीरता एवं शीघ्रता से समाधान निकालना होगा। आज नहीं तो कल हर कोई इसका शिकार होगा। यह एक चुनौती भी है। सभी को सचेत रहना होगा।

-प्रवीण वर्मा, गरियाबंद

ट्रेंड

राहत और बचाव कार्य जारी

कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एसडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम जम्मू-कश्मीर वासियों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मूल्यानुगत शिक्षा

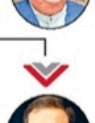

जब हम आंतरिक शांति की बात करते हैं तो मूल्यानुगत शिक्षा को केंद्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। आज की तकनीकी जिंदगी में नागरिक मूल्यों से जुड़ी शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है।

-जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

वोट चोरी की साजिश

जनता की ताकत है उसका वोट - यही उसका हक, उसकी आवाज, उसकी पहचान है। आज वही ताकत छीनी जा रही है, एसआईआर के जरिए देश में वोट चोरी की साजिश चल रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी रोकेंगे!

-राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

आमूलचूल परिवर्तन

चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज लोकतंत्र को बचाने का ज़िम्मेदारी दायित्व उनके कंधों पर है। लगता उनके ऊपर कोई प्रकार के आशीर्वाद दबाव काम कर रहे हैं लेकिन वो ये न समझें कि वो अंधेरे में हैं।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से नहीं घटता वाहनों का माइलेज

पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन ' ई-20 '' के इस्तेमाल से वाहनों का माइलेज घटने की चर्चाओं के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ईंधन दक्षता में भारी गिरावट आने की आशंकाएं निराधार हैं और इस ईंधन से वाहन बेहतर प्रदर्शन भी देता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गन्ना या मक्का से निकाले गए 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल के मिश्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदूषण कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से है, जिसे कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों के बीमा की वैधता पर भी कोई असर नहीं पड़ता है और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इस संबंध में फैलाया गया डर बेबुनियाद है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ई-20 ईंधन को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि इसके इस्तेमाल से वाहन के माइलेज में करीब सात प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि कुछ लोगों ने इससे ई-10 वाहनों में रबर, धातु कलपुर्जों के जल्द खराब होने की आशंका जताई है। मंत्रालय ने कहा, यह कहना कि ई 20 ईंधन से वाहन की दक्षता में 'भारी' कमी आती है, गलत है।

ऑफ बीट

कुत्ते पढ़ सकते हैं आपका दिमाग और चेहरा

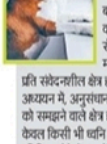

जब आप रोते हैं तो आपका कुत्ता अपना सिर झुका लेता है, जब आप तनाव में होते हैं तो इधर-उधर टहलता है, और आपके सबसे बुरे पलों में किसी न किसी तरह आपके पास होता है। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता। हजारों सालों के सह-विकास ने कुत्तों को हमारी आवाजों, चेहरों और यहां तक कि मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को समझने के खास तरीके दिए हैं। हमारी बातचीत को समझने वाले मस्तिष्क के क्षेत्रों से लेकर हमारी नजरें मिलाने पर बढ़ने वाले 'लव हार्मोन' या ऑक्सीटोसिन तक, आपके कुत्ते का दिमाग आपकी भावनाओं को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमाण मस्तिष्क में ही शुरू होता है। कुत्तों के मस्तिष्क में आवाज के प्रति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जो इंसानों के समान होते हैं। एक 'ब्रेन इमेजिंग' अध्ययन में, अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कुत्ते के 'टेम्पोरल कॉर्टेक्स' में आवाज को समझने वाले क्षेत्र होते हैं, जो ध्वनियों के जवाब में सक्रिय हो जाते हैं। कुत्ते न केवल किसी भी ध्वनि पर, बल्कि आपकी आवाज के भावनात्मक स्वर पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्तों के मस्तिष्क के अध्ययन से पता चलता है कि भावनात्मक ध्वनियां, मसलन हंसी, रोना, गुस्से से चीखना उनके श्रवण और भावनाओं को समझने से संबंधित मस्तिष्क के एक हिस्से को सक्रिय करती हैं।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस्ट्रीज पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

कल्पमेधा

शुभ और अशुभ हमारे मन पर अवलंबित हैं। जब मन स्थिर और शांत होता है, तो शुभ-अशुभ उसे छू भी नहीं पाते हैं।

- स्वामी विवेकानंद

कसौटी पर पुनरीक्षण

लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चलाने की वैधता हासिल करना नहीं, बल्कि यह उस बुनियाद का प्रमुख स्तंभ है, जिस पर देश या राज्य की पूरी व्यवस्था का दारोमदार टिका होता है। इस प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर उठे सवालों का जवाब भी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पास ही है। मगर, सवाल यह है कि क्या आयोग के जवाब से आमजन, सामाजिक संगठन और संबंधित राजनीतिक दल संतुष्ट हो पाए हैं? साफ है कि ऐसा नहीं हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अब शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह एसआइआर के तहत मसविदा मतदाता सूची से हटाए गए पैंसठ लाख नामों को कारण सहित सार्वजनिक करे।

चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा कई स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की सूची संबंधित राजनीतिक दलों के साथ पहले से साझा की जा रही है। हालांकि, विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्हें आधी-अधूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। सवाल यह भी है कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है और उसके पीछे क्या कारण हैं, इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को कैसे मिल पाएगी? क्या हर व्यक्ति के लिए अपने स्तर पर सूची में अपना नाम दर्ज होने या न होने की पुष्टि करना संभव है? इसी पहलू को ध्यान में रखकर शीर्ष अदालत ने बिहार में मसविदा सूची से हटाए गए नामों की सूची पंचायत स्तर के कार्यालय और जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। साथ ही नाम हटाने के कारणों का पूरा ब्योरा देने को भी कहा है। जाहिर है, इससे उन मतदाताओं को आसानी से अपना दावा करने की सहूलियत होगी, जो मतदान के योग्य होने के बावजूद किसी कारणवश सूची से बाहर हो गए हैं।

सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है, वे अपने आधार कार्ड के साथ निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं। पहले चुनाव आयोग आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से सहमत नहीं था। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले से पंजीकृत 22.34 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 36.28 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं और अब उनका पता मालूम नहीं है तथा करीब सात लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। मगर, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों की संख्या की पुष्टि का ठोस आधार क्या था, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही यह सवाल भी अनुत्तरित है कि अगर कोई व्यक्ति स्थानांतरित हो जाता है, तो क्या उस राज्य में मतदान करने का उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है? यह बात सही है कि बिहार ही नहीं, बल्कि तमाम राज्यों में मतदाताओं के एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने की समस्या पैदा हुई है। मगर, चुनाव आयोग पहल करे तो सब कुछ डिजिटल होने के दौर में इस तरह की समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली वाली संस्था है, लेकिन ये शब्द सिर्फ कागजों में सहेजने के लिए नहीं हैं, धरातल पर इनके मूल्य और महत्त्व नजर आने से ही लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो पाती है।

कठघरे में चुनाव

पिछले काफी समय से देश में स्वतंत्र, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव के लिए लगातार आवाज उठाई जाती रही है। खासतौर पर ईवीएम के जरिए मतदान और मतों की गिनती को लेकर कई बार संदेह जाहिर किए गए। ऐसे आरोप सामने आए कि इसमें तकनीकी गड़बड़ी के जरिए या मतगणना में हेरफेर करके नतीजे प्रभावित किए जाते हैं। विडंबना यह है कि जब भी इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, तो आमतौर पर उन्हें निराधार मान कर खारिज कर दिया जाता है। दलील यह होती है कि जो उम्मीदवार हारता है, केवल उसे ही शिकायत होती है। जरूरी नहीं कि ऐसे सभी आरोप सही साबित हों। मगर इसी बीच अगर कहीं से मतगणना और नतीजों में हेरफेर की कोई शिकायत हर स्तर की जांच-पड़ताल के बाद अंतिम तौर पर सही पाई जाए, तो ऐसे में समूची प्रणाली भी संदेह के घेरे में आती है। जाहिर है, इसके बाद फिर नतीजे और उसके आधार पर बनी सरकारें भी कठघरे में होती हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के पानीपत जिले के ग्राम पंचायत बुआना लखू में सन 2022 में हुए सरपंच के चुनाव के बाद जब नतीजों की घोषणा हुई, तभी इस पर विवाद उठा था। वह मामला तब जिला अदालत से होते हुए आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

ऐसी शिकायतें अब तक शायद ही किसी अंजाम तक पहुंची हों। मगर इस मामले में शीर्ष अदालत के फैसले ने पहली बार ईवीएम से चुनाव और मतगणना पर उठने वाले सवालों को मजबूत आधार दिया है। दरअसल, इस मामले में अदालत ने खुद ईवीएम मंगवा कर अपनी निगरानी में मतों की फिर से गिनती करवाई और पहले के नतीजे से अलग परिणाम घोषित किया। इसमें परिणाम पलट गया और पहले हार चुके प्रत्याशी को सरपंच बनाया गया। जाहिर है, शीर्ष अदालत की इस कवायद के बाद अब ईवीएम के जरिए डाले गए मत और उसकी गिनती से लेकर किसी प्रत्याशी की जीत-हार की घोषणा तक की समूची प्रक्रिया की पारदर्शिता पर अगर सवाल उठते हैं, तो उसे बेमानी या निराधार घोषित कर पाना मुश्किल होगा। इस पूरे मामले से यह भी जाहिर होता है कि किसी चुनाव की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, ताकि विवाद की स्थिति में उनकी जांच हो और सारे संदेह दूर किए जाएं।

नाम नहीं, काम की संस्कृति

भारत एक युवा देश है और इसकी आधी आबादी कार्यशील उम्र अवधि में है। इसलिए अगर यह आधी आबादी काम पर या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दुनिया के दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी।

सुरेश सेठ

भारत बहुत प्राचीन देश है। यहां की सांस्कृतिक विविधता ही हमारी पहचान है। आजादी का शतकीय महोत्सव, जो हम वर्ष 2047 में मनाने वाले हैं, उसके लक्ष्य में भी यही इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखकर विश्वगुरु की भूमिका निभाए। वर्तमान सरकार की भी यह घोषणा है कि अपने देश में जिस विकास की नींव हम रख रहे हैं, उसका सुफल हजारों वर्षों तक मिलेगा तथा हमारी सांस्कृतिक गरिमा और भव्यता बनी रहेगी। बहुत-सी बातें हैं जिनके बल पर हम इस दावे को प्रमाणित करना चाहते हैं। भारत एक युवा देश है और इसकी आधी आबादी कार्यशील उम्र अवधि में है। इसलिए अगर यह आधी आबादी काम पर या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। मगर, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रशस्ति गायकों का यह मत है कि हम दुनिया के विभिन्न देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं और अब जरूरत है अर्थव्यवस्था में कुछ और सुधार करने की। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे।

अब देखना यह है कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग क्या देश में काम की संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण रपट आई है, जिसमें विभिन्न देशों की मेहनत वृत्ति या काम करने की अवस्था का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम आधी आबादी काम के बजाय आराम करना पसंद करती है, क्योंकि मुफ्तखोरी और अनुकंपा संस्कृति का चलन बढ़ रहा है। एक और बात सामने आई है कि भारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को श्रेय या पारिश्रमिक ही नहीं मिलता है। जैसे महिलाएं इस देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर की मेहनत को घर का सामान्य कामकाज ही समझा जाता है। इस काम के लिए उन्हें अलग से कोई नियत वेतन नहीं मिलता। ये महिलाएं दिनभर काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने लिए कोई अलग आर्थिक संबल प्राप्त नहीं कर पातीं।

इसमें संदेह नहीं कि आज भी जो बेकारी के आंकड़े सामने आते हैं, उनमें ग्रामीण बेरोजगारी के बाद शहरी बेरोजगारी में भी वास्तविक अर्थों में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही। चाहे औपचारिक घोषणाओं में हम यह कहते रहें कि हमने हजारों खाली पद भर लिए हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितने खाली पद भरे, बल्कि देश की युवा संतति के कामकाज के लिए कितनी नई कार्य व्यवस्थाएं सृजित की गईं। देश के वार्षिक बजट के आय-व्यय ब्योरे में हम कितनी उन नई योजनाओं की घोषणा कर पाए, जिनमें युवा पीढ़ी को काम मिले। बेशक बजट में और इसके बाद नेताओं के भाषणों में यह कहा जाता है कि देश में मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इनमें साधारण नागरिकों को रोजगार देने की क्षमता है। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया कि देश में सहकारिता की भावना को विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक से

अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन जब हम वास्तविकता का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास में भी बड़े पूंजीपतियों के निवेश का प्रवेश हो गया है, क्योंकि, सरकार की नीति निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की है।

> **देश के वार्षिक बजट के आय-व्यय ब्योरे को देखें तो हम कितनी उन नई योजनाओं की घोषणा कर पाए, जिनमें युवा पीढ़ी को काम मिले। बेशक बजट में और इसके बाद नेताओं के भाषणों में यह कहा जाता है कि देश में मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इनमें आम नागरिक को रोजगार देने की क्षमता है। मगर, जब हम वास्तविकता का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास में भी बड़े पूंजीपतियों के निवेश का प्रवेश हो गया है, क्योंकि, सरकार की नीति निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की है।**

सहकारिता आंदोलन के विकास के बारे में बहुत से औपचारिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सहकारिता की भावना को किसी भी समर्पित स्तर पर देश में अपनाया नहीं जा सका है। न तो कृषि और न ही उद्यम क्षेत्र में। देश में नवउद्यमों की बहुत बात होती है। नवउद्यम ये उद्योग हैं, जिनमें नए निवेशकों को काम करने का अवसर मिलता है और नवाचार या नव अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन नवउद्यमों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। धनी लोग जो बैंकिंग सहायता से इन उद्योगों में सक्रिय योगदान दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कम हो रही है। कृत्रिम मेधा और डिजिटल क्षेत्र के विकास के साथ-साथ अल्प पूंजी वाले निवेशकों का फीसद इसमें कम होता जा रहा है।

उधर, शुल्क संघर्ष में विदेशी व्यापार इस तरह से करवट बदलता नजर आ रहा है कि लगता है भारत के निवेशकों को लागत पूरा न होने और निर्यात घटने के संशय से औद्योगिक सक्रियता कम करनी होगी। इसीलिए अब जो नए आंकड़े रेटिंग एजंसी मूडीज की ओर से आए हैं, उनमें यह कहा गया है कि भारत की इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.5 फीसद से कम होकर छह फीसद तक रह सकती है। यह कोई संतोष की बात नहीं है कि हमारी विकास दर अभी भी दुनिया में सबसे अधिक है। देखना होगा कि जो पीढ़ी काम कर सकती है, क्या इस विकास दर ने उन्हें काम दिया? अगर आय और संपदा का समुचित बंटवारा हो जाता, तो निश्चय ही यह विकास दर बेरोजगारों को रोजगार देती।

आजकल लगता है कि देश में वादा संस्कृति या नाम संस्कृति का बोलबाला हो गया है। अभी सरकार की ओर से बयान आया कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। यह बयान तो पहले ही आ गया था कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य का यह बड़प्पन क्या देश में काम करने वालों के लिए काम की संस्कृति पैदा कर रहा है? क्या हमने देश के हर नौजवान के लिए उसकी योग्यता के अनुसार काम के अवसर सृजित किए हैं? जवाब है, नहीं। यह बात सच है कि हमने किसी भी व्यक्ति को भूख से न मरने देने की गारंटी दे रखी है। इस गारंटी को पूरा करने के लिए हमने रियायती रेवड़ियां बांटना जारी रखा है। इसके लिए सभ्य नाम उदार संस्कृति है और आर्थिक नाम अनुकंपा संस्कृति है। वर्ष 2029 तक हमने सस्ता खाद्यान्न प्रदान करने की नीति को बढ़ा ही दिया है। असर यह हुआ है कि नौजवानों का दबाव रोजगार खिड़कियों से हटकर रियायती अनाज बांटने वाली खिड़कियों की ओर हो गया है।

ज्यों-ज्यों चुनावी एजंडों में नई अनुकंपा योजनाओं की घोषणा होती है, त्यों-त्यों भारत के दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाने की संभावना मजबूत होती है, जो अपनी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटता है। मगर, अपने आप में क्या यह कार्य संस्कृति से हटना नहीं? जापान और चीन ने जितनी तरक्की की है, वह इसीलिए संभव हो सका कि वहां काम की संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है। हमारे यहां तो नाम संस्कृति कह लीजिए या रेकार्ड बनाने की संस्कृति कि हमने सबसे अधिक आबादी को रियायती अनाज दे दिया। ऐसे में जरूरी है कि काम की तलाश में विदेश जा रही हमारी युवा पीढ़ी को देश में ही राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। मगर, उसके लिए देश के नीति निर्माताओं को घोषणा संस्कृति से हटकर कार्य संस्कृति को लेकर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और प्राथमिकताओं की तस्वीर को जरूरत के हिसाब से बदलना होगा।

मौन के पार

अलका 'सोनी'

पेड़ की डाल पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट मन मोह लेती है। भंवरों की गुंजन से प्रभावित होकर सूरदास ने 'भ्रमरगीत प्रसंग' ही लिख डाला था, तो बच्चों की तोतली बोली हमें अनायास हंसाने पर मजबूर कर देती है। सच तो यह है कि वाणी प्राणियों को प्रकृति से मिला एक अनूपम उपहार है, जिसकी वजह से हम अपनी बातों और मनोभावों को दूसरों तक सहज ही प्रेषित कर पाते हैं। मगर इस वाणी के भी अपने दायरे हैं। बच्चों के मुख से निकली अटपटी बातें किसी का हृदय विच्छिन्न नहीं करतीं, लेकिन बड़ों के मुंह से निकली अनर्गल बातें युद्ध के हालात खड़े कर देती हैं। दरअसल, बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और कितना बोलना है, यह समझने में समय लगता है। सच यह है कि नरम ढंग से भी इस दुनिया को बदलने में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है।

संवाद की ताकत की अपनी अहमियत है। क्रोध या चिल्लाहट नहीं, बल्कि विनम्र संवाद ही स्थायी परिवर्तन लाता है। संवाद वह डोर है, जो दिलों को जोड़ती है। जब दो लोग खुलकर अपने विचार, भावनाएं, दुख-सुख और अपेक्षाएं साझा करते हैं, तो रिश्तों में पारदर्शिता आती है। यही पारदर्शिता विश्वास को जन्म देती है और जो रिश्ते को जड़ को मजबूत करता है।

यह संवाद केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं होता। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक सहमति में हिलाया गया सिर भी बहुत कुछ कह जाता है, जिससे रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। मगर जब हम मौन ओढ़ लेते हैं गुस्से, अहं या डर में, तब धीरे-धीरे रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ने लगती है। वे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पौधों को नम, सींची हुई माटी न मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्नेह से सींची हुई जमीन चाहिए होती है। फिर हम सब तो इंसान हैं, जिसका वजूद ही रिश्तों से है। कहते हैं कि जहां संवाद नहीं, वहां संदेह पनपता है। यह पंक्ति पूरी तरह सच लगती है, क्योंकि बातों से मन की गांठें खुलती हैं। मतभेद दूर होते हैं और लोग एक-दूसरे के नजदीक आते हैं।

रिश्ते, चाहे पति-पत्नी के हों, माता-पिता और बच्चों के हों, मित्रता के या सहकर्मियों के, इन सभी की बुनियाद संवाद पर ही टिकी होती है। संवाद यानी केवल बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और दिल से महसूस करना। जब संवाद का पुल टूटता है, तब रिश्तों में गलतफहमियां, संदेहों और दूरी की दरारें उभरने लगती हैं। एक वृद्ध दंपति के बीच लंबे समय से बातचीत बंद थी। कारण क्या था, दोनों को अब याद भी नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने-अपने मौन को 'मान' का नाम दे रखा था। एक दिन वृद्ध महिला बीमार पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृत्यु शैया पर वह अपनी कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाई कि 'काश! मैंने फिर एक बार तुमसे बात की होती!' वृद्ध पुरुष की आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि वे भी यही चाहते थे, लेकिन संवाद के अभाव ने दोनों को सिर्फ मौन में कैद कर रखा था। फिर जब मौन की दीवार टूटी भी तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे दृश्य शायद हम सभी अपने जीवन में और आसपास देखते हैं, जहां एक जगह रहते हुए और संवाद करने की सभी संभावनाओं के बाद भी हम मौन के उस पार नहीं जा पाते। 'मैं क्यों बोलूं पहले', 'गलती उसकी है', जैसे विचार हम पर हावी रहते हैं। ये विचार ही संवाद की राह में सबसे बड़ी दीवार बनते हैं। जब दोनों पक्ष पहले क्षमा मांगने या पहल करने से इनकार कर देते हैं, तब और चुप्पी गहराने लगती है। आज हर दिन मर रहे इंसानी रिश्तों के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं।

रही-सही कसर आजकल मोबाइल पूरा कर दे रहा है, जब लोग मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा और एक-दूसरे की आंखों में कम झांकते हैं। सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत संवाद को एक तरह से ग्रहण लगा दिया है। सच कुछ 'व्यक्तिगत' होता जा रहा है, जहां किसी को भी, किसी के इस तथाकथित व्यक्तिगत जीवन में झांकने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि मां-बाप को भी नहीं, भले ही बाजार उनकी सारी निजता छीन ले। इसके कारण संवाद लगभग शून्य होते जा रहे हैं। बिना संवाद के दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी हो जाते हैं। यहां समझने की जरूरत है कि बिना बात किए मन की बात को नहीं समझा जा सकता। इससे व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में उलझता है और रिश्ते बिगड़ते हैं। संवादहीनता से व्यक्ति भीतर ही भीतर घुटता जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> **संवाद केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं होता। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक सहमति में हिलाया गया सिर भी बहुत कुछ कह जाता है, जिससे रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। मगर जब हम मौन ओढ़ लेते हैं गुस्से, अहं या डर में, तब धीरे-धीरे रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ने लगती है और वे मुरझाने लगते हैं।**

इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि रिश्तों के बीच इस मौन और संवादहीनता को पनपने ही नहीं दिया जाए। रिश्तों में मौन अक्सर गलतफहमियों, अनकहे दर्द या अहंकार के कारण पनपता है। जब संवाद रुकता है, तो रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। संवादहीनता को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम है धैर्य से सुनना। न केवल शब्दों को, बल्कि भावनाओं को भी। दूसरे की बात को समझने का प्रयास करने की जरूरत है। प्रतिक्रिया देने से पहले महसूस करना चाहिए।

इस संदर्भ में प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस का कहना है कि 'ईश्वर ने हमें दो कान और एक मुंह दिए हैं, ताकि हम बोलने से ज्यादा सुन सकें।' यह कथन रिश्तों में संवाद की मूल भावना को दर्शाता है, जिसमें संवाद का एक बड़ा हिस्सा बोलने से ज्यादा सुनने में निहित बताया गया है। जब हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को समझने का मार्ग खुलता है और मौन धीरे-धीरे पिघलने लगता है। रिश्तों को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रकृति से मिले उपहार 'वाणी' की महत्ता और मर्यादा दोनों बनी रहे।

उपहारों की परंपरा

हमारे समाज में शादी, जन्मदिन या किसी अन्य खुशी के अवसर पर दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाना पुरानी परंपरा है। हम उन्हें इस भावना से आमंत्रित करते हैं कि वे हमारी खुशी में शामिल हों और इस पल को हमारे साथ साझा करें। लेकिन समय के साथ एक ऐसी आदत बन गई है कि इन अवसरों पर मेहमानों से उपहार लेने की उम्मीद की जाती है, मानो यह एक अनिवार्य सामाजिक नियम हो। अगर विचार करें, तो यह खुशी का अवसर हमारा होता है, तो मेहमानों पर उपहार लाने का बोझ डालना क्या उचित है? हमने उन्हें अपनी खुशी का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है, ऐसे में हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम उनका अच्छे से स्वागत करें, स्वादिष्ट भोजन कराएं और अपनी तरफ से उन्हें कुछ यादगार भेंट दें। आज उपहार देना और लेना औपचारिकता एवं दबाव में बदल गया है। कई मेहमान केवल सामाजिक मजबूरी के कारण उपहार देते हैं। वहीं, आयोजक भी इसे अपना हक मानने लगे हैं। खुशी तभी बढ़ती है, जब उसे बांटा जाए, न कि लेन-देन में बदला जाए। परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए, ताकि वे रिश्तों में मिठास बढ़ाएं।

-मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

सकारात्मक संकेत

'महंगाई से राहत' (संपादकीय, 14 अगस्त) पढ़ा। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर का आठ साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आना आम नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए सकारात्मक संकेत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों का असर अब बाजारों में दिखाई देने लगा है। हालांकि, भविष्य में भी महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है और यह आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डाल सकती है। असल में खुदरा महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण बेहतर मानसून और खरीफ की अच्छी बुवाई से खाद्य कीमतों में आई स्थिरता है। मगर खाद्य तेलों के बढ़ते दाम अभी भी चिंता का विषय हैं। स्थायी राहत के लिए महंगाई में कमी केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि बाजार की कीमतों में भी दिखनी चाहिए।

- अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

दोहरे मापदंड

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 'सूट वाला उसामा बिन लादेन' कहा है। उनके हिसाब से मुनीर के परमाणु धमकी देने वाले बयान से तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान उपद्रवी राष्ट्र जैसा व्यवहार कर रहा है। मुनीर ने अमेरिका में जाकर यह कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अगर उसने इस्तेमाल किए, तो वह अपने साथ विश्व की आधी आबादी को भी ले डूबेगा। दूसरी ओर, सभी को इस बात पर भी आश्चर्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी मुनीर को अपने देश में बुलाकर उनके साथ रात्रिभोज करते और उनका सम्मान भी करते हैं। इसलिए अब साफ है कि अमेरिका हमारे साथ दोहरी चाल चल रहा है। कारण जो भी हो, एक तरफ वह पाकिस्तान को पुचकारता है, तो दूसरी ओर वह उसे दुत्कारता भी है। यह बात समझने और सजग रहने की जरूरत है।

- मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर

संवेदना और सुरक्षा

इन दिनों कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। आए दिन वे कभी बुजुर्गों पर, तो कभी महिलाओं पर, तो कभी मासूमों पर हमला करते हैं। वाहनों के पीछे भौंकते और दोपहिया वाहनों के पीछे दौड़ते कुत्तों को अक्सर देखा जा सकता है। दिल्ली-एनसीआर में भी आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में भेजने का आदेश दिया है। यह भी कहा कि इनकी नसबंदी कर उसी इलाके में छोड़ना बिल्कुल बेतुका है। कुत्तों के काटने के आंकड़ों पर नजर डालें, तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दिल्ली में कुत्ते के काटने के सालाना औसतन 25 हजार मामले सामने आते हैं। इसी तरह भोपाल में हर वर्ष 20 हजार मामले आते हैं। कुछ भी हो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में शीर्ष न्यायालय की चिंता बेवजह नहीं है।

- योगेश जोशी, कंचर कालोनी, बड़वाह

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 155

आर्थिक वृद्धि को मिलेगी धार

लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को लगातार 12वीं बार संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी बल्कि, ये भारत को एक अधिक सुरक्षित राष्ट्र बनाने में भी मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी घोषणाएं की हैं उनमें अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक कार्यबल का गठन करना भी शामिल है। यह कार्य बल एक निश्चित समय सीमा में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों, नियम-शर्तों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा।

किंतु याद रहे कि पीएम मोदी ने पहले एक विनियमन आयोग की स्थापना की भी बात कही थी मगर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई। नियम एवं दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा से कारोबार संचालन में सुगमता काफी बढ़ सकती है। सरकार अब इस पर काम भी कर रही है और लगभग 40,000 से अधिक अनावश्यक प्रावधान और 1,500 से अधिक पुराने कानून निरस्त कर चुकी है। हालांकि, 21वीं शताब्दी की आवश्यकता के अनुरूप नियम एवं दिशानिर्देशों को धार देने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जरूरत है। इस प्रक्रिया में राज्यों को भी अवश्य साथ लिया जाना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगले चरण के सुधारों को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। जीएसटी व्यवस्था में संभवतः ज्यादातर वस्तु एवं सेवाएं दो कर श्रेणियों (5 फीसदी और 18 फीसदी) में आ जाएंगी, जबकि हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की एक अलग कर श्रेणी तैयार की जाएगी। यह कदम जीएसटी में कर संरचना सरल बना देगा और नियमों का अनुपालन भी मजबूत हो जाएगा। कुछ अन्य श्रेणियां वर्गीकरण एवं प्रक्रियात्मक विषयों से भी संबंधित होंगी। कर संरचना सरल बनाने और दरों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी मगर जिस संरचना का प्रस्ताव दिया गया है उसमें राजस्व के आंकड़ों पर असर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्व से जुड़े पहलुओं का बेहतर तरीके से प्रबंधन करना होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता का भी जिक्र किया, जो वर्ष 2014 से सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक रही है। कोविड महामारी के बाद राजकोषीय मजबूती पर सरकार के ध्यान और व्यय की उच्च गुणवत्ता के बाद रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ग्लोबल ने 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत की सॉवरिन रेटिंग बढ़ा दी है। रेटिंग में सुधार से भारत निवेश के दृष्टिकोण से आकर्षक हो जाएगा विशेषकर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। हालांकि, निकट अवधि में निवेश की दशा एवं दिशा अमेरिका के साथ व्यापार के मोर्चे पर जारी तनाव से प्रभावित होगी। फिलहाल देश की आर्थिक वृद्धि के लिए व्यापार से जुड़ी अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा है। इसी संदर्भ में मोदी ने कहा है कि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। ऐसी खबरें आती रही हैं कि अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ता में कृषि क्षेत्र दोनों देशों के बीच असहमति की एक बड़ी वजह रही है। रूस से तेल आयात के लिए अमेरिका ने जब से भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही है तब से स्थिति और पेचीदा हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत को अपने किसानों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह क्षेत्र देश की आधी आबादी के लिए जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत है। मगर यह क्षेत्र अन्य देशों के साथ भी व्यापार वार्ताओं में विवाद का एक प्रमुख विषय रहा है।

लिहाजा, सही संतुलन स्थापित करने के लिए स्थिति का मूल्यांकन बेहद आवश्यक है। यह माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी बात करेंगे। इस संबंध में उन्होंने 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है। यह मिशन न केवल देश के लिए सुरक्षा आवरण तैयार कर हमले से रक्षा करेगा बल्कि पूरी ताकत के साथ दुश्मन के हमले का जवाब भी देगा। इस प्रणाली पर शोध और इसका विकास भारत में ही होगा। प्रधानमंत्री ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए एक जनसांख्यिकीय अभियान शुरू करने का भी घोषणा की। इस पर किसी तरह के बहस की गुंजाइश नहीं है कि पड़ोसी देशों से लोगों को अवैध रूप से भारत में घुसने और रहने नहीं देना चाहिए। किंतु, इस मिशन में इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं पिछड़े लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। कुल मिलाकर, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए और तेज गति के साथ आगे बढ़ना होगा। वर्तमान में व्यापार से जुड़े विषय सुलझाना बड़ी प्राथमिकता है, वहीं जीएसटी सुधार एवं अगली पीढ़ी के व्यापाक सुधारों की घोषणाएं संभावित आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

भारत बनाम पाक वायु सेना संख्या नहीं सिद्धांतों की जंग

मई में हुई जंग में दोनों देशों की वायु सेना ने एक दूसरे के विमान मार गिराने के दावे किए हैं। क्या यह बात वाकई मायने रखती है कि किसने किसके कितने विमान मार गिराए?

मैं इस पूरे मामले की शुरुआत एक पेचीदा प्रश्न से कर सकता हूं। वह प्रश्न यह है कि अगर युद्ध में एक पक्ष ने 13 विमान गंवा दिए और दूसरे पक्ष के 5 विमान नष्ट हो गए तो आखिर जीत किसकी हुई? भारत-पाकिस्तान के सभी सक्रिय युद्धों एवं झड़प की अवधि काफी कम रही है। 1965 में दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध 22 दिनों तक खिंचा था। 'ऑपरेशन सिंदूर' तो महज तीन दिन से थोड़ा अधिक चला। जब भी आत्मसमर्पण एवं सामूहिक समर्पण जैसे निर्णायक नतीजे नहीं दिखते हैं तो दोनों पक्षों के पास जीत का दावा करने की गुंजाइश मौजूद रहती है।

हालांकि, कुछ स्थितियों में तस्वीर बिल्कुल साफ रही है। हम भारतीय मानते हैं कि सभी युद्ध या झड़प में हम विजयी रहे हैं, मगर यह स्वीकार करते हैं कि 1962 की लड़ाई चीन से हार गए थे। ठीक इसी तरह, पाकिस्तान के लोग 1971 में हुई हार स्वीकार करते हैं। अब यह जानते हैं कि 1971 में किस वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में युद्ध के दौरान कितने विमान खो दिए?

टेल नंबर (विमानों की विशिष्ट पंजीकरण संख्या) और पायलट के नामों के साथ जो आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं उनके अनुसार भारत को 13 और पाकिस्तान को 5 विमानों का नुकसान हुआ। कोई भी इन आंकड़ों पर अंगुली नहीं उठाता। ये सभी विमान युद्ध में मार गिराए गए थे न कि दुर्घटनाओं का शिकार हुए।

अब हम फिर उसी पेचीदा सवाल पर आ जाते हैं। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी वायु सेना (पीएएफ) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक विमान युद्ध में खो दिए। भारत के जब इतने विमान गिर गए तो फिर युद्ध कौन जीता? क्या यह सवाल पूछने लायक भी है? आईएएफ को इन 13 विमानों का नुकसान कैसे हुआ? इनमें दो हवाई युद्ध में गिराए गए (जैसा कि पीएएफ के 5 विमानों के साथ हुआ) और शेष जमीन से दागे गए छोटे हथियारों के निशाने पर आ गए।

पीएएफ के मैदान छोड़ने के बाद भी आईएएफ के लिए युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसने सेना को ताकत देने और उसका नुकसान कम करने के लिए जोखिम की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आईएएफ के 13 में से 11 विमान बहुत नीचे उड़ान भरते हुए पाकिस्तान की सेना द्वारा जमीन से दागे गए हथियारों के निशाने पर आ गए। दोनों वायु सेनाओं के बीच यह मूलभूत अंतर है। एक रक्षात्मक हवाई जंग एवं अपने बचाव को लेकर जुनूनी है तो दूसरी व्यापक राष्ट्रीय प्रयास के लिए एक आक्रामक रुख अपनाती है। पीएएफ संख्या को लेकर जुनूनी है तो आईएएफ अंतिम नतीजे को अधिक तवज्जो देती है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

पीएएफ और पाकिस्तानी जनमत के लिए केवल यह बात मायने रखती है कि उन्होंने कितने विमान मार गिराए हैं। माहौल इतना खुशनुमा है कि पाकिस्तान के लोग इसे अपनी वायु सेना की जीत मान रहे हैं मगर इसका सेहरा सेना प्रमुख के सिर बांध दिया है और उन्हें हास्यास्पद रूप से फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया।

इन बातों से दोनों वायु सेनाओं के बीच सैद्धांतिक दृष्टिकोण में अंतर साफ झलकता है। पीएएफ अपनी आत्मरक्षा पर अधिक केंद्रित उस मुक्केबाज की तरह है जो पीछे हटते हुए अपना चेहरा छुपाकर प्रतिद्वंद्वी के हमले का इंतजार करती है और मौका देख दांव चलती है। इसके उलट आईएएफ आक्रामकता के साथ पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ती है और कुछ चोट खाने के लिए भी तैयार रहती है। अगर पीएएफ जोखिम से बचने में लगी रहती है तो आईएएफ जोखिम लेने में विश्वास करती है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के तीन उद्देश्य थे। पहला, मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों को नेस्तनाबूद करना। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा किसी भी जवाबी हमले को रोकना और बचाव करना। और तीसरा, अगर वह ऐसा करना जारी रखता है तो उसे करारा जवाब देना। आईएएफ ने इन तीनों उद्देश्यों को पूरा कर लिया। जैसा कि कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने कहा कि शुरू में कुछ नुकसान जरूर हुआ था। पहले और तीसरे उद्देश्यों की पूर्ति होने के सबूत के तौर पर भारत ने बहुत साफ तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं।

पीएएफ 6 और 7 मई की दरमियानी रात में पहले 22 मिनट में अपनी कथित हवाई-से-हवाई 'सफलता' के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेगी। पीएएफ इसी मानसिकता में जीती रही है। अगर आपकी नजर पीएएफ द्वारा उक्त घटना पर दिए विवरण पर रही है तो गौर करेंगे कि 'स्थिति जन्य जागरूकता' का बार-बार इस्तेमाल हुआ है। जाहिर है, यह हवाई युद्ध के बारे में ही बात करती रहेगी। मगर वास्तविकता यह है कि 15 दिन पहले चेतावनी मिलने के बावजूद पीएएफ अपने किसी भी ठिकानों की रक्षा नहीं कर पाई।

यह आईएएफ के जंगी विमानों को चुनौती नहीं दे सकी। आईएएफ ने सिंधु के पूर्व और उसके दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में पीएएफ के ठिकानों, हवाई रक्षा स्थानों और महत्त्वपूर्ण हथियार भंडारों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें बरसाईं। पीएएफ लड़ाई के लिए कभी तैयार ही नहीं थी।

भारतीय सैन्य विमानन इतिहासकार एवं विश्लेषक पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा, रवि रिब्बे ने स्विस-ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ पीटर स्टीनमैन के साथ 1991 में अपनी पुस्तक 'फिजा'यः साइकी ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स' में इस विचित्र मानसिकता का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पीएएफ वास्तविक हालात और उसी के शब्दों में परिस्थितिजन्य जागरूकता से पूरी तरह अलग-थलग है।

उन्होंने अपनी पुस्तक में पीएएफ की मानसिकता के बारे में आगे कहा है कि वह अपनी भूमिका हवा से हवा में युद्ध तक ही सीमित देखती है और अपनी क्षमता का ख्याल कर इस बात से अपनी सफलता निर्धारित करती है कि उसने प्रतिद्वंद्वी के कितने विमान गिरा दिए हैं। इसके बाद वह अपनी बची-खुची ताकत युद्ध के अंतिम चरण के लिए बचा कर रखती है। इसका मतलब है कि पीएएफ केवल एक खास स्वार्थ के लिए युद्ध करती है और बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बनने से दूर रहती है। पाकिस्तान युद्ध हार जाएगा लेकिन पीएएफ तब भी अपनी जीत का खोखला दावा करेगी क्योंकि उसने तो 'अधिक विमानों को मार गिराया।' पीएएफ ने तीन महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अपने किसी भी दावे के समर्थन में सबूत या तस्वीर का एक भी टुकड़ा पेश नहीं किया है। वह इसके लिए कोई बहाना भी नहीं बना सकती क्योंकि आजकल तो वाणिज्यिक उपग्रह भी सब कुछ देख रहे होते हैं। पाकिस्तान फिर भी जीत का जश्न मना रहा है। इसकी मीडिया (मुख्यधारा और सोशल दोनों), सभी दलों के राजनेता और बेशक सेवारत सैन्य अधिकारी एवं पूर्व रणनीतिकार एक बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ तो यह दंभ भी भर रहे हैं कि 1971 का बदला ले लिया गया है और खुद को पदोन्नति, पदक और सम्मान से नवाज रहे हैं।

आईएएफ और पीएएफ के इस सैद्धांतिक अंतर के पीछे कई उदाहरण, इतिहास और मानसिकता हैं। आइए, पहले भारत के हवाई युद्धों से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। प्रत्येक मामले में भारत ने पाकिस्तान की तुलना में युद्ध में अधिक विमान खोए हैं। संक्षेप में कहें तो यदि हम इकाई, प्रकार, टेल नंबर, चालक दल के नाम, स्थान और युद्ध में बंदी बनाए गए चालक दल के लोगों के नामों की फेहरिस्त तैयार करते हैं तो 1965 के युद्ध में भारत के 52 विमान मार गिराए गए जबकि पाकिस्तान के 20 विमान नष्ट कर दिए गए। 1971 की लड़ाई में भारत को 62 विमान गंवाने पड़े जबकि पाकिस्तान के 37 विमान तबाह हो गए। ये विशुद्ध रूप से युद्ध में हुए नुकसान हैं जिसमें विमान हवा में निशाना बनाए गए या प्रतिद्वंद्वी वायु सेना द्वारा जमीन पर नष्ट कर दिए गए।

पीएएफ 1965 में अपनी कथित जीत के लिए 6 सितंबर को 'पाकिस्तान रक्षा दिवस' के रूप में मनाती है। यह कार्यक्रम एकतरफा पीएएफ से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि उस दिन उन्होंने सरगोधा पर आईएएफ के कई हमलों को विफल कर दिया और कई विमानों को मार गिराया। यह सब इतना काल्पनिक और भावनाओं से ओत-प्रोत है कि कई पढ़े-लिखे पाकिस्तानी भी पूछ बैठते हैं कि अगर पीएएफ इतनी प्रभावशाली थी तो पाकिस्तान युद्ध क्यों नहीं जीत पाया? सवाल तो अच्छा है।

कड़वी सच्चाई तो यह है कि 6 सितंबर वह दिन था जब पाकिस्तान युद्ध हार गया। कश्मीर पर कब्जा जमाने के उसके ऑपरेशन जिब्राल्टर और फिर ग्रैंड स्लैम विफल हो गए। पाकिस्तान की मंशा कामयाब नहीं हो पाई और उसके बाद उसने सारा जोर अपनी रक्षा करने में लगा दिया। यही वजह है कि यह दिन पाकिस्तान रक्षा दिवस के रूप में मनाता है।

1971 के युद्ध में क्या हुआ और कौन विजयी रहा इस पर कोई संशय नहीं हैं। क्या पीएएफ केवल इस आधार पर जीत का दावा कर सकती है कि उसने लड़ाई में कम विमान खोए? पाकिस्तान के लोग अगर ईमानदारी से आत्ममंथन करेंगे तो वह जरूर पूछेंगे कि पीएएफ आत्मरक्षा करने के बजाय आगे बढ़कर युद्ध करती तो क्या उसने राष्ट्रीय प्रयास में अधिक योगदान नहीं दिया होता?

किसी भी लड़ाई में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें पीएएफ का पलड़ा भारी रहा हो। पीएएफ ने अगर वाकई कुछ किया तो यह कि अपनी सेना और नौसेना दोनों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया। यह पीएएफ की उस मानसिकता पर मुहर लगती है कि वह केवल अपने लिए, अपने द्वारा और ज्यादातर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ती है। पीएएफ केवल इसी भूमिका के लिए तैयार की गई है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में भी ऐसा ही हुआ।

शुल्कों के बीच ट्रंप के नरम-गरम रुख के मायने

अमेरिका-भारत शुल्क विवाद से जुड़ी कई अटपटी बातें गिनाई जा सकती हैं। मगर उनमें सबसे अधिक अटपटा यह है कि भारतीय तेल शोधन कारखानों (रिफाइनरी) से अमेरिका को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह तब है जब ट्रंप ने रूस से भारत के तेल खरीद पर दंड के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया है। रूस से खरीदे जाने वाले तेल एवं गैस भारत के पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लुब्रिकेंट्स के निर्यात के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। अमेरिका द्वारा रूस से यूरेनियम यौगिकों और उर्वरकों के आयात पर काफी कुछ लिखा जा चुका है, इसलिए इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

मगर निवेश और व्यापार के नजरिए से यह स्पष्ट है कि अमेरिका और भारत दोनों में से किसी को शुल्कों से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। भारत के लिए नुकसान यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बाजार तक उसकी पहुंच बाधित हो जाएगी और इसके उत्पाद वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी नहीं रह जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग कम हो जाएगी। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच 129 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का व्यापार हुआ था। अमेरिका से भारत को 42 अरब डॉलर और भारत से अमेरिका को 87 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ था।

अमेरिकी उपभोक्ता (और अमेरिका स्थित विनिर्माता) जो भी आयात करेंगे और जिस भी देश से करेंगे उन पर उन्हें भारी भुगतान करना होगा। निर्माता और आयातक ऊंचे शुल्क के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ा देंगे और यह सिलसिला शुरू भी हो चुका है। उदाहरण के लिए टाटा समूह बोइंग के लिए विमान के फ्यूजलेज (मुख्य ढांचे) का निर्माण करता है। यह ऐसा कार्य है जिसके विनिर्माता आसानी से नहीं बदले जा सकते। लिहाजा, बोइंग अपने विमान महंगे कर सकती है।

देवांशु दत्ता

उत्पादों के दाम बढ़ने के बाद अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ जाएगी जिससे मांग पर चोट पड़ेगी। इसका मतलब यह भी होगा कि अमेरिका खपत पर चोट पड़ने से राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त शुल्क राजस्व हासिल नहीं कर पाएगा।

अब इस बात पर नजर डालते हैं कि शुल्क बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? कई क्षेत्र अपने उत्पाद अमेरिका को निर्यात कर मोटा राजस्व अर्जित करते हैं। दवा, वाहन पुर्जा और परिधान आदि क्षेत्रों को तगड़ा नुकसान होगा। जो क्षेत्र अमेरिकी बाजारों में अपने उत्पाद अधिक नहीं भेजते हैं वे दूसरे बाजारों की तलाश करेंगे। शुल्क अंतिम रूप लेने के बाद शेयर बाजार कुछ समय तक गिरावट झेलेगा और फिर हालात के साथ तालमेल बैठा लेगा।

अमेरिका में भारतीय निवेशक वाले कारोबारों जैसे नोवेलिस (हिंडाल्को की सहायक कंपनी) को आपूर्ति व्यवस्था नए सिरे से तैयार करनी होगी। नोवेलिस फिलहाल कनाडा (जो स्वयं अमेरिकी शुल्कों की चपेट में आ गया है) से कच्चे माल मंगाती है। इसी तरह, जिन वाहन कंपनियों (जैसे महिंद्रा समूह) की अमेरिका में सहायक इकाइयां हैं उन्हें पुर्जे आदि मंगाने के नए तरीके खोजने होंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे सीमेन्स और एबीबी के लिए भी कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वैश्विक मूल्य व्यवस्था में उनकी भारतीय इकाइयां भी शामिल हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की मांगें पूरी करना असंभव है। राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार के लिए देश के कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलना संभव नहीं है। ऐसा भी कोई तरीका नहीं है जिससे भारत अपने व्यापार संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाए बिना रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। अगर भारत अमेरिका से तेल एवं गैस खरीदेगा (जैसा कि अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है) तो उसके लिए लागत बढ़ जाएगी और ढुलाई एवं अभियांत्रिकी से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा।

भारत के पास ट्रंप का मन बदलने की कोशिश करने के लिए कुछ ही विकल्प हैं जिन्हें वह आजमा सकता है। अमेरिका के साथ सौदेबाजी करने के लिए मोदी सरकार में चीन की तरह जवाबी शुल्क लगाने की हिम्मत नहीं है। भारत अमेरिका से रक्षा उत्पाद खरीदने की पेशकश कर सकता है और फिर नवंबर 2026 में अमेरिका में सीनेट के चुनाव के बाद ट्रंप के कमजोर पड़ने की सूरत में अपने वादे से पीछे हट सकता है। रक्षा साजो-सामान की आपूर्ति में लंबा समय लगता है। उदाहरण के लिए अगर भारत इस सप्ताह के अंत में कुछ एफ-35 विमानों के ऑर्डर देता है तो पहले एफ-35 की आपूर्ति में कई साल लग जाएंगे। लिहाजा, रक्षा सौदे करने की गुंजाइश मौजूद है और शुल्क की समस्या खत्म होने पर इन्हें रद्द किया जा सकता है।

यह स्थिति हमें दो अन्य पहलुओं से जुड़ी राजनीति की तरफ ले जाता है। ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना शुल्क लगाने में कानूनी रूप से सक्षम नहीं हैं। फिलहाल इस मोर्चे पर उनके लिए समस्या नहीं है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के पास प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत है। ट्रंप की नीतियां अगर जनता को अधिक सताने लगीं तो इस बात की अच्छी-खासी संभावना होगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा और संभवतः सीनेट में भी खेल पलट दे। लिहाजा नवंबर 2026 तक शुल्क का दर्द सहना पड़ सकता है।

अनुभवी एवं जानकार लोगों को याद होगा कि कारोबारी 'ग्रीनस्पैन पुट' की किस नजरिये से देखते थे। जब भी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख एलन ग्रीनस्पैन (जो 1987 से 2006 तक प्रमुख रहे) के दौर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजरती थी तो वे पेचीदा बयान देते थे मगर मुद्रा की आपूर्ति आसान बना देते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ग्रीनस्पैन क्या कह जाते थे मगर अच्छी बात यह होती थी कि वह मुद्रा आपूर्ति जरूर सहज बना देते थे। कुछ कारोबारी अब 'टैको पुट' (ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट) की बात कर रहे हैं। ट्रंप अक्सर सख्त रवैया अपनाते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। जब तक यह सिलसिला जारी रहेगा तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या कहते हैं।

आपका पक्ष

वर्षा जनित तबाही से मकानों की सुरक्षा जरूरी

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में अक्सर भारी बारिश एवं बादल फटने से तबाही होती है जिसके कारण काफी जन-धन हानि होती है। कई बार तो गांव के गांव बाढ़ में बह जाते हैं। कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में भी इसी तरह की तबाही एवं बरबादी से काफी जन-धन हानि हुई थी। हाल में इसी क्षेत्र में हुई घटना ने एक बार फिर केदारनाथ में हुई उस त्रासदी की याद दिला दी है। इस बार हुई दुर्घटना में भी काफी जन-धन की हानि हुई है तथा कई घर बह गए। अतः केंद्र सरकार को ऐसी जन-धन हानि रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों में बनने वाले आवासों की मजबूती पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर आवास मजबूत होंगे तो जन-धन हानि को कम किया जा सकता है। इस क्षेत्र में बनने वाले आवासों को मजबूत बनाने के लिए सरकार को विदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भी मदद लेनी चाहिए। अगर आने वाले समय में इस क्षेत्र में मजबूत एवं सुरक्षित आवास बनेंगे तो यहां बार-बार आने वाली तबाही को रोका जा सकता है।

मनमोहन राजावत, शाजापुर

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में रविवार को बादल फटने और भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई। सेना ने राहत के लिए हेलीकॉप्टर लगाए।

प्लास्टिक की जगह अपनाएं प्राकृतिक विकल्प

प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा जरूर बन गया है लेकिन इसका असर आज मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि 1950 से अब तक प्लास्टिक उत्पादन 200 गुना बढ़ चुका है और अगले 35 वर्षों में इसके तीन गुना होने की आशंका है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले समय की भयावह तस्वीर है। माइक्रो-प्लास्टिक हमारे भोजन, पानी और हवा में घुलकर शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। कैंसर, हार्मोन असंतुलन, हृदय रोग और बांझपन जैसी समस्याएं अब असामान्य नहीं रहीं। इस संकट से बचने के लिए सिंगल- यूज प्लास्टिक पर कड़ा प्रतिबंध लगाना होगा। उद्योगों को मजबूर करना होगा कि वे प्राकृतिक विकल्प और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग अपनाएं। उत्पादन और उपभोग दोनों पर अंकुश जरूरी है।

अमृतलाल मारू, इंदौर

वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही के कारण जान-माल की हानि होती है। इसे कई वर्षों से रोकने हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं मगर दुर्घटनाएं कम नहीं हुईं। सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे लोगों की आए दिन दुर्घटना की खबर आती है। अधिकांश लोग वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग करते हैं और उनका ध्यान बातचीत पर ही रहता है। पीछे से आ रही हॉर्न की आवाज पर भी वह ध्यान नहीं देते जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सीसीटीवी कैमरे लगा कर चालान की कार्यवाही की जानी चाहिए। निर्धारित गति से ज्यादा गति में वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना और यातायात के नियमों का पालन नहीं करना आदि को लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इन छोटे-छोटे उपायों का पालन करने से हम सुरक्षित रह सकते हैं।

संजय वर्मा, धार

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में यातायात की भीड़ कम करने के उद्देश्य से लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग-दो (यूईआर-दो) का उद्घाटन किया।

स्वतंत्रता दिवस

भारत का विचार

1947 में आज ही के दिन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना नियति से मिलन भाषण दिया था। यह अपने वाले वर्षों के लिए, नेताओं और आम जनता, दोनों के लिए एक रोडमैप था। उस भाषण का एक भावपूर्ण वाक्य था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। बड़ा सवाल यह है: क्या हमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, या हम उसे पूरा करने के अपने लक्ष्य के करीब हैं? और वह प्रतिज्ञा क्या थी? वह भारत का विचार था, जिसे संविधान की प्रस्तावना में बहुत खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है: हमारा लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समानता; और बंधुत्व को बढ़ावा देना है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। एक ऐसा देश जहां जनता सर्वोपरि है, और उनके कल्याण, सम्मान और आकांक्षाओं को महत्व दिया जाता है।

निष्पक्षता से कहें तो यह कहना गलत होगा कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन हां, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, खासकर सामाजिक न्याय, सम्मान और सभी के लिए समानता के क्षेत्र में। हर 15 अगस्त को, तिरंगा आसमान में लहराता है और राष्ट्र उसे याद करने के लिए रुकता है। राष्ट्रगान की धुनें हवा में तैरती हैं, स्कूल के मैदान देशभक्ति के गीतों से गूंजते हैं और सड़कें केसरिया, सफेद और हरे रंगों से जगमगा उठती हैं। यह कैलेंडर की एक तारीख से कहीं बढ़कर है, यह भारत की पहचान का धड़कता हुआ दिल है। हर साल, जब हम झंडे के नीचे इकट्ठा होते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि आजादी न तो उपहार में मिली थी और न ही किसी ने इसे यूं ही छीन लिया था, इसे बलिदान, एकता और आत्मनिर्णय के

अधिकार में अटूट विश्वास के जरिए औपनिवेशिक शासन की कठोर पकड़ से छीना गया था। औपनिवेशिक शासन सिर्फ. राजनीतिक अधीनता से कहीं ज्यादा था, यह सम्मान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर हमला था।

उनहत्तर साल बाद, यह यात्रा प्रेरणादायक और जटिल दोनों रही है। भारत विभाजित राज्यों वाले एक नवजात लोकतंत्र से एक प्रभावशाली वैश्विक आवाज के रूप में विकसित हुआ है। साक्षरता दर अथवन चुनाई है, जीवन प्रत्याशा दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, और अर्थव्यवस्था अभाव से बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमारे अंतरिक्ष मिशन चांद और मंगल तक पहुँचते हैं, हमारे उद्यमी वैश्विक कंपनियां बनाते हैं, और हमारा लोकतंत्र, अव्यवस्थित होते हुए भी लचीला, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है।

फिर भी, ये सारी उपलब्धियां दलितों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार, और धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय आधार पर एक खंडित, ध्रुवीकृत समाज से प्रभावित हैं। गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन आज भी उन्हीं आदर्शों को चुनौती देते हैं जिनके लिए हमने संघर्ष किया था। न्याय, समानता और समृद्धि का गांव अभी पूरे तरह से तय नहीं हुआ है। हमारे औपनिवेशिक अतीत की गूंज कभी-कभी फिर से उभर आती है झ नौकरशाही की जड़ता में, जड़ जमाए सामाजिक पदानुक्रमों में, और अवसरों तक असमान पहुँच में। लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहनशीलता, अनुकूलन और फिर से उठ खड़े होने की क्षमता में निहित है। 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने का मतलब अपनी कमियों को नजरअंदाज करना नहीं है बल्कि उन पर विजय पाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। यह चार रखना है कि स्वतंत्रता स्थिर नहीं है, यह एक जीवंत जिम्मेदारी है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी, इसे मजबूत करना होगा, तभी इसकी पहुंच उन लोगों तक बढ़ानी होगी जो अभी भी हाशिये पर हैं।

एआई और भारत का चुनावी भविष्य

बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा है, ऐसे में यह तकनीक अवसर और खतरे, दोनों को लेकर चलती है: यह मतदाताओं की भागीदारी को सुव्यवस्थित कर सकती है और जनभावनाओं का विश्लेषण कर सकती है, साथ ही यह डीपफेक, गलत सूचना और हेराफेरी को भी बढ़ावा देती है।

कल्याणी शंकर
लेखिका, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं।

पिछला साल एक हाई-प्रोफाइल चुनावी साल था जिसमें 60 देशों में मतदान हुआ। इसमें भारत भी शामिल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मतदान प्रतिशत का अनुमान लगाने, संभावित मतदाताओं की पहचान करने, मतदाताओं की प्राथमिकताओं का आकलन करने और अधिकतम प्रभाव के लिए चुनाव प्रचार कार्यक्रम को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे एआई चुनावी साल कहा गया। जैसा कि सुरखा गुरु श्नाइयर ने सही कहा था, लोकतंत्र केवल गतियों के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मानवीय प्रक्रिया के बारे में है। समर्थकों का दावा है कि एआई इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए है, न कि इसे बदलने के लिए।

इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भारत में एआई फिर से सक्रिय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, और राजनीतिक दल इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि किसे जीत मिलती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों ही राजनीतिक दल आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन, जनता दल (युनाइटेड) अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयासरत है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे-धीरे भारत और दुनिया भर के चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर रही है, इस लहस के बीच कि यह अभिशाप है या वरदान।

विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर-के मतदाताओं को लक्षित किया जा रहा है। उल्लेखनीय रूप से, कई बेखबर मतदाता उनके सामने आने वाली जानकारी या गलत सूचना पर विश्वास करने को तैयार हैं। एआई में तेजी से हो रही प्रगति के साथ, दुनिया भर में चुनावी गतिविधियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं।

इसने इस बारे में गंभीर चर्चाओं को जन्म दिया है कि एआई राजनीतिक अभियानों, मतदाता जुड़ाव और चुनाव प्रबंधन को कैसे बदल सकती है।

राजनीतिक दल नए तरीकों से तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मतदाताओं की भावनाओं का विश्लेषण करने, मतदान प्रतिशत की भविष्यवाणी करने और यहां तक कि व्यक्तिगत अभियान संदेश बनाने के लिए एआई का उपयोग किया गया। भारत के 2024 के चुनावों को एआई चुनाव कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं से बात करने और उनके सवालों के जवाब देने के लिए एआई प्लेटफॉर्म ममो का उपयोग करते हैं। वह एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर कई रैलियों में भाषण देने के लिए होलोग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं।

यह तकनीक मोदी को बिना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। आगामी बिहार चुनावों में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जो राजनीतिक अभियानों को बेहतर बनाने के नए तरीके प्रदान करता है, जैसे लक्षित विज्ञापन, मतदाताओं की राय का विश्लेषण और मतदान प्रतिशत का अनुमान लगाना।

ये उपकरण अभियानों को अधिक कुशल और प्रभावी बना सकते हैं। हालांकि, वे चुनौतियाँ भी लेकर आते हैं। एआई मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में उपयोगी जानकारी खोजने में मदद करता है, लेकिन यह गलत जानकारी भी फैलाता है। कई मतदाताओं को प्राप्त होने वाले संदेशों

एआई में तेजी से हो रही प्रगति के साथ, दुनिया भर में चुनावी गतिविधियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। इसने इस बारे में गंभीर चर्चाओं को जन्म दिया है कि एआई राजनीतिक अभियानों, मतदाता जुड़ाव और चुनाव प्रबंधन को कैसे बदल सकती है।

और कॉल की प्रामाणिकता सत्यापित करने में कठिनाई होती है। भारत में 2024 के चुनावों में, राजनीतिक दलों ने एआई का इस्तेमाल करके नकली ऑडियो और वीडियो समर्थन, लक्ष्यात्मक सामग्री और झूठा प्रचार तैयार किया, जो ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो।

एआई मतदाता जुड़ाव में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। इस दौरान, बनाई गई सामग्री का केवल लगभग 2 प्रतिशत ही एआई से आया। यह छोटी सी मात्रा मुख्य रूप से मतदाताओं तक पहुँचने और उन्हें शामिल करने पर केंद्रित थी।

यह चुनावों में एआई के सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है और सुझाव देता है कि यह मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ने में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के अलावा, एआई चैटबॉट उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। उम्मीदवार मतदाताओं के सवालों का जवाब दे सकते हैं और उनकी चिंताओं का सीधे समाधान कर सकते हैं।

वे अपने अभियानों को बेहतर बनाने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान भी दे सकते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं की पृष्ठभूमि, मतदान इतिहास और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर व्यक्तिगत संदेश भेज सकते हैं। 2024 के चुनाव भविष्य के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम करेंगे। परिणाम उठने चौंकाने वाले नहीं थे जितना कई लोगों ने अनुमान लगाया था, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण जोखिम दिखाए क्योंकि जानकारी को विकृत किया जाना जारी है। 2024 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट एआई द्वारा उत्पन्न गलत सूचना, मतदाता हेरफेर और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास के क्षरण जैसे संभावित खतरों पर प्रकाश डालती है।

चुनाव आयोग द्वारा एआई का उपयोग चुनाव प्रबंधन को बेहतर बनाने, चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और चुनाव प्रबंधन में सुधार के लिए किया जाता है। हालांकि, सभी फायदे और नुकसान के साथ, चुनावों और अन्य क्षेत्रों में एआई के उचित विनियमन की आवश्यकता है।

अभी तक, यह बहुत अधिक नहीं है। न केवल भारत, बल्कि अन्य देशों ने भी कुछ समय पहले यूके में एक सम्मेलन आयोजित किया था; भारत ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। हाल ही में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उचित नियमों की मांग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के खतरों के बारे में बताया और पारदर्शी नियमों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामग्री के प्रकटीकरण का आह्वान किया।

चुनावों के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई तरह से मददगार हो सकती है। उदाहरण के लिए, फिकलनोट एक ऐसा उपकरण है जो नीति-निर्माण में सहायता करता है। यह मतदाताओं से उनकी पसंदीदा नीतियों के बारे में जानकारी भी एकत्र कर सकता है।

इसी तरह, आईसाइडविट उम्मीदवारों को अपने बारे में जानने और यह देखने का अवसर देता है कि क्या वे मतदाताओं के विचारों से मेल खाते हैं।

मानवीय जुड़ावों में परिप्रेक्ष्य की ताकत

अपने मन को सकारात्मक गुणों पर केंद्रित करने से हम स्वतः ही नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, जो उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं।

ब्रह्म कुमार विक्रुंज
लेखक, अध्यात्मिक उपदेशक हैं।

मानवीय रिश्ते बेहद जटिल और संभालने में मुश्किल होते हैं, इसलिए इन्हें निभाने के लिए अपार धैर्य, समझ, स्वीकृति, स्वीकारोक्ति और जुड़ाव की जरूरत होती है। एक मशहूर कहावत है कि हम चीजों को उनके वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक रूप में देखते हैं। हालांकि हमारी भौतिक आंखें हर चीज और हर किसी को एक ही नजर से देखती हैं, लेकिन असल में देखने की क्रिया के साथ आने वाले विचार और भावनाएं ही हमारे मन में उस चीज के बारे में एक धारणा बनाती हैं जो हम देख रहे हैं। इसलिए, अगर हमारी भावनाएं हल्की और शुद्ध हैं, तो हम जो कुछ भी देखते हैं, उसके बारे में वैसा ही महसूस करते हैं।

दूसरी ओर, अगर हम नकारात्मक मनोदशा में हैं, तो हम चीजों को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब हम दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम उनके प्रति आसानी से बुरी भावनाएं या नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। वास्तव में, हमेंयें से ज्यादातर लोग इस मामले में अनुभवी हैं, है ना? इससे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि हम उस व्यक्ति में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो हमें पसंद हैं, और जल्द ही हमारी भावनाएँ बदलने लगेंगी।

संक्षेप में, अपने मन को सकारात्मक गुणों पर केंद्रित करने से हम स्वतः ही नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, जो उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं।

लेकिन अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमें एहसास होता है कि जिस पर हम अपना इतना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, वह हमारी जिंदगी की यात्रा में एक छोटी सी बात है और दुनिया या ब्रह्मांड के विशाल मंच पर घटित हो रही घटनाओं के संदर्भ में तो और भी ज्यादा महत्वहीन हो जाता है।

याद रखें! यह हम पर निर्भर करता है कि हम हर चीज के प्रति एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखें या एक संकीर्ण दृष्टिकोण जो हमारे जीवन को दुखी बना दे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी-छोटी असुविधाओं या रिश्तों में आने वाली समस्याओं को कैसे लेते हैं। हम या तो उनके बारे में सोचते रह सकते हैं, उन्हें बड़ी समस्याएँ बना सकते हैं और अंततः बोझिल, निराश, क्रोधित या उदास महसूस कर सकते हैं या हम उन्हें सही नजरिए से देख सकते हैं और उनसे सर्वोत्तम तरीके से निपट सकते हैं, बिना उन्हें अपनी मनःस्थिति को प्रभावित करने दिए। ऐसा दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करते हुए स्थिर रहने में मदद करता है।

यह हमारे आस-पास के लोगों की भी मदद करता है, क्योंकि यह हमें आत्म-केंद्रित या स्वार्थी सोच से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भलाई के बारे में सोचने में सक्षम बनाता है। यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और हमें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति एक अच्छा टीम वर्कर बनता है, दूसरों के स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने और हर तरह के लोगों के साथ काम करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के अच्छे गुणों की सराहना भी करेगा और उनसे सीखेगा।

वे ईर्ष्या से मुक्त होंगे, दूसरों की प्रशंसा सुन सकेंगे, और बिना परेशान हुए सही भावना से सलाह और आलोचना स्वीकार कर सकेंगे। चूंकि ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की परिस्थितियों का स्थिर मन से सामना कर सकता है, इसलिए उन पर जिम्मेदारी का भरोसा किया जाएगा और वे दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत होंगे।

और चूंकि वे कभी भी छोटी-छोटी बातों में नहीं उलझते और हमेशा बड़े परिदृश्य को देखते हैं, इसलिए दूसरों को भी उनके निष्पक्ष निर्णय पर विश्वास होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी समूह या संगठन में एक एकीकृत व्यक्ति होगा, और विभाजनकारी गुटों या गुटों के गठन या गठबंधन के जाल में नहीं फँसेगा। हमारी चेतना में एक साधारण बदलाव लाने के ये अद्भुत लाभ हैं।

अब, यह हम पर निर्भर है कि हम अपने भले के लिए बदलाव करें, या भ्रमित, दुखी और उदास रहें।

आप की बात

अविस्मरणीय नेताजी सुभाष

18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 80 में पुण्यतिथि है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे तेजस्वी और साहसी विभूतियों में से एक थे। उनका जीवन केवल संघर्ष और त्याग का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का अमर स्वरूप भी है। आजादी के लिए उनका शक्तिशाली नीचा और स्पष्ट था झ हम्मनतंत्रता भिक्षा में नहीं, संघर्ष में मिलती है। उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी कर विदेशी शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का शंखनाद किया। उनका व्यक्तित्व, साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्हें विश्व के महानतम नेताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। आज जब उनके पार्थिव अवशेषों को भारत लाने की चर्चा हो रही है, तब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या नेताजी को मनोचित्रत भारत रज से सम्मानित किया जाए। यह गौर करने योग्य तथ्य है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसे अब तक अनेक राजनेताओं, समाजसेवियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को दिया गया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस सम्मान का वास्तविक अधिकारी है तो वह निस्संदेह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। स्वतंत्र भारत की नींव केवल असहयोग और अहिंसा से नहीं, बल्कि नेताजी जैसे क्रांतिकारियों के साहसिक प्रयासों से भी मजबूत हुई। उनकी भूमिका ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया।

– सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

चारों ओर हादसे

चाहे टीवी चैनल हो या समाचार पत्रों के समाचार में जिधर देखो उधर सड़क हादसों की खबरें सुनायी की तरह आ रही है। इन खबरों को देख व पढ़कर हाथ-पैरों के साथ-साथ मन-मस्तिष्क सुन्न पड़ जाते है। सड़कों पर यह होने वाले हादसे रोजमर्रा की बात बन गई है। इन हादसों में परिवार के परिवार साफ हो रहे हैं। उसके बाद भी कोई सबक नहीं। ना सिस्टम कुछ कर रहा है, ना वाहन चलाने वाले, कोई जरीहत लेने को तैयार हैं। कोई ओवर स्पीड का शिकार हो रहा है, तो कोई ओवरटेक का, तो कोई नशे में स्वयं के साथ-साथ निर्दोषों की भी बलि ले रहा है, तो कोई सड़कों पर स्टंट बाजी कर जान को खो, ले रहा है। नाबालिग भी पिछे नहीं रह रहें हैं। कहीं सिस्टम की अवहेलो के चलते गड्ढे भी मौत का कारण बन रहें हैं। जीते जी काश तर्क की खातमां झेल रही है, तो तर्क की खातमाओं से भी बहुत मौतें सड़कों पर हो रही है। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब कुछ निर्बाध चल रहा है, चलता रहेगा। अब तो कुछ सोचों, समझों। जीवन अनमोल है। इसको कोई-मकोई की तरह गंवाना, ईमानी समझदारी भी तो नहीं है। न ओवर स्पीड, न बेतरतीब ओवर टेक, न स्टंट बाजी, न नशें में ड्राइविंग, न नाबालिगों के हाथों में वाहन, ऐसा संकल्प जरूरी है। सिस्टम को भी हड़ इच्छाशक्ति के साथ मौत के गड्ढों व जानलेवा सड़कों की बेतरतीब डिजाइन को सुधारना होगा।

– हेमा हरि उपाध्याय, अमत खाचरोद, उज्जैन

अब भी जेल में कृष्ण परिवार

एक समाचार के अनुसार 23 वर्षों से गूपी में कानपुर (देहात) के सिकती कस्बे के थाने में बलराम, कृष्ण और राधा की मूर्तियां बल खाने में कैद है जिन्हें पुलिसकर्मी सिर्फ एक दिन जन्माष्टमी पर उन्हें बाहर लाकर, वए वस्त्र पहनाकर पूजा-अर्चना करके पुनः मालखाने में पहुंचा देता है कानूनी प्रक्रियाओं के चलते"। ड्यूर दुर में कृष्ण का जन्म गन्ध-देवकी पर कंस के अत्याचारों के चलते कारागृह में ही हुआ किन्तु ईश्वरीय (मानवीय) स्वरूप में चमत्कारिक/मायाजाल रूप से वे वहां से बाहर आ गए, किन्तु कलयुग में 23 वर्षों से कोर्ट के कठपुतली माणाजाल में फंसकर मूर्ति रूप में परिवार सहित बेचारे कृष्ण-राधा-बलराम तीनों कारागृह में ही सजा काट रहे हैं. केवल एक दिन की एक साल में उन्हें पेरोल मिलती है और उन्हें गाजा-धूलाकर पूजा-अर्चना व भोजन (प्रसाद) करके वापिस मालखाने में पहुंचा दिया जाता है (मजेदार बात यह है कि यहाँ चोरों ने तब मूर्तियां चुराई थी, तब पुलिस द्वारा उसे बरामद किया गया, चोरों को सजा हुई और वे जेल से छूट भी गए पर मूर्तियां पुलिस कस्टडी में न्याय की प्रतीक्षा अभी भी कर रही है 23 वर्षों से) ये कलयुग है बाबा जहाँ 'मूर्ति रूपक 'भरवान' को ही नहीं बख्शा है कानून की लम्बी प्रक्रियाओं के चलते तब इंसान की क्या बिसात कि वे जीतेजी न्याय पा ले. भगवान राम को किन्तु कलयुग में उनकी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के लिए करीब 500 साल तक कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा।

– शकुंतला महेश नेताबा, इंदौर

अलास्का से उठा सवाल

जब विश्व की निगाहें अलास्का के एंकोरेज पर टिकी थीं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रूस-यूक्रेन युद्ध को शांत करने की उम्मीद जगा रही थी, तब भारत सहित दुनिया सांस थामे प्रतीक्षा में थी। तीन घंटे की गहन वार्ता बेनतीजा रही। ट्रंप का कथन, समझौता तभी, जब वास्तव में समझौता हो, और पुतिन का युद्ध के मूल कारणों पर जोर, वैश्विक कूटनीति की जटिलता को उजागर करता है। भारत, शांति का प्रतीक, इस विफलता को चुनौती और अवसर के रूप में देखता है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। भारत ने रूस से रियायती तेल आयात बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, पर वैश्विक अस्थिरता ने चुनौतियां खड़ी कीं। क्वाड और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक संबंध भारत को नाजुक संतुलन की राह पर ले गए। प्रधानमंत्री मोदी का कथन, यह युद्ध का युग नहीं, भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अवसर देता है। भारत, जो रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रखता है और यूक्रेन को मानवीय सहायता देता है, अपनी तटस्थता को मजबूत कर सकता है। यह असफल वार्ता भारत को कूटनीति तेज करने का मौका देती है। भारत को तटस्थ स्थिति उसे वैश्विक मंच पर मध्यस्थ बनाती है। युद्ध के लंबा खिंचने से भारत स्वतंत्री रहा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है।

– आरके जैन, अरिजीत, बड़वानी

विविधता में ही समाज की एकता निहित है।
-जॉर्ज हर्बर्ट मीड

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली जीएसटी संरचना में अगली पीढ़ी के लिए जिन सुधारों का उपहार देने की घोषणा की है, वे ठीक से अमल होने पर व्यापार को सरल और पारदर्शी तो बनाएंगे ही, इनसे 2047 तक विकसित राष्ट्र होने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी चमक भी अर्थव्यवस्था को मिलेगी।

जीएसटी की दूसरी पारी

प्रधानमंत्री मोदी की इस दिवाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संरचना में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा निश्चित ही स्वागतयोग्य है और यह व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, जो लंबे समय से इस कर प्रणाली की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 में लागू हुआ जीएसटी देश की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसने विभिन्न केंद्रीय व राज्य करों को एकीकृत कर व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास किया। एक अच्छी मंशा के साथ लागू इस व्यवस्था ने सरकार को कमाई तो बहुत कराई, लेकिन इसकी बहुस्तरीय स्लैब-संरचना और अनुपालन की जटिल प्रक्रियाओं ने खासकर छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए खासी चुनौतियां खड़ी कीं। आलम यह है कि लागू हुए आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी कारोबारी इसकी जटिलताओं को समझने की क्षमता पूरी तरह नहीं जुटा पाए हैं। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों विश्व बैंक इसे दुनिया की सबसे जटिल कर व्यवस्था कहता है। गौरतलब है कि जीएसटी के मूल कानून में अब तक 900 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और अब तक हुई जीएसटी परिषद की तकरीबन सभी बैठकों में नियमों को बदला गया है। जाहिर है कि ये स्थितियां जीएसटी में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत की ओर ही इशारा करती हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के दलों को संसद में करने के प्रस्ताव को राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को भेजे जाने की खबरें हैं। ऐसे समय में, जब अमेरिकी टैरिफ माहौल को अनिश्चित और आशंकापूर्ण बना रहे हैं, तब जीएसटी में प्रस्तावित सुधार अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर सकते हैं। सरल कर-ढांचा व्यापार की लागत को कम करने के साथ वैश्विक निवेशकों के लिए भी भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाएगा। कीमतों में स्थिरता आने से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हालांकि, सुधारों का यह मार्ग आसान नहीं होगा। विभिन्न हितधारकों, खासकर

राज्यों की राजस्व हानि की चिंताओं को देखते हुए, उनके साथ समन्वय की चुनौती होगी। कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत एकल जीएसटी स्लैब की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सभी के लिए उपयुक्त सार्वभौमिक दर तय करना आसान नहीं होगा। ऐसे में, सरकार को व्यापक परामर्श, डाटा विश्लेषण और तकनीकी नवाचारों की जरूरत होगी। उम्मीद है कि अगले महीने संभावित जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी के दूसरी पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगी, जो देश के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा की दृष्टि से अपरिहार्य भी है।

तमिल संस्कृति के वास्तविक ध्वजवाहक

तमिल संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का वास्तविक ध्वजवाहक कौन है? जिन्होंने सनातन संस्कृति के प्रति घृणा का प्रचार-प्रसार किया या फिर वे महान सूर्यवंशी चोल सम्राट, जिन्होंने समृद्धिशाली व्यवस्था के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया तक उस संस्कृति का ध्वज फहराया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों हुए तमिलनाडु प्रवास का निहितार्थ क्या है? इस यात्रा को उनके प्रशंसक और आलोचक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी की प्राचीन बृहदेश्वर शिव मंदिर की तीर्थयात्रा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे भाजपा की राजनीति मानता है, जिसके अंतर्गत पार्टी तमिलनाडु में अपना जनाधार सुदृढ़ करना चाहती है। वस्तुतः इस यात्रा का महत्व इन दोनों से कहीं अधिक व्यापक है। चोल राजवंश और इसके दो महाप्रतापी सम्राटों-राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम की गौरवगाथाओं को पुनर्जीवित कर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 'द्रविड़ आंदोलन' की आड़ में पनपाई जा रही अलगाववादी-विषैली विचारधारा और उससे प्रेरित राजनीति के ध्वस्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भारत की सांस्कृतिक एकता, विरासत और ऐतिहासिक गौरव जैसे बिंदुओं को पुनः केंद्र में लाने की कोशिश है।

बलबीर पुंज
पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

अपने दो दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन किया। इसके उपरांत उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम स्थित सहस्राब्दी-प्राचीन बृहदेश्वर शिव मंदिर में दर्शन किए और 'आदि तिरुचिथिरई' महोत्सव में सम्मिलित होकर भारत के महानतम सम्राटों में से एक-राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की भी घोषणा की।

राजेंद्र चोल प्रथम कौन थे? भारत के इतिहास में उनका वही स्थान है, जो सम्राट अशोक और राजा विक्रमादित्य का है। वे गर्वित तमिल थे, दृढ़प्रतिज्ञ शिव भक्त थे और प्राचीन तामपत्री-शिलालेखों, जो कि तमिल के साथ संस्कृत में भी लिखित हैं-उनमें इस बात का उल्लेख है कि चोल सम्राट स्वयं को मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम काल से सूर्यवंशी परंपरा (इक्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चंद्र और भगीरथ सहित) का वंशज मानते थे। वैदिक काल से सूर्यवंशियों का भगवान शिव के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है। तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम इसका सबसे बड़ा मूर्त रूप है। गोस्वामी

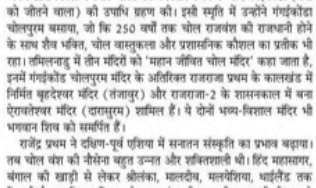

तुलसीदास द्वारा रचित *रामचरितमानस* के अनुसार, *'सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुं मोहि न पावा। संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी।'* अर्थात-श्रीराम कहते हैं, जो शिव से द्रोह रखते हैं...वे मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते।

जिस भव्य गंगईकोंड मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए, उसका निर्माण चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर-भारत तक विस्तार करने के बाद गंगईकोंडा (गंगा को जीतने वाला) की उपाधि ग्रहण की। इसी स्मृति में उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम बसाया, जो कि 250 वर्षों तक चोल राजवंश की राजधानी होने के साथ शैव भक्ति, चोल वास्तुकला और प्रशासनिक कौशल का प्रतीक भी रहा। तमिलनाडु में तीन मंदिरों को 'महान जीवित चोल मंदिर' कहा जाता है, इनमें गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के अतिरिक्त राजराजा प्रथम के कालखंड में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर) और राजराजा-2 के शासनकाल में बना ऐरावतेश्वर मंदिर (दारासुरम) शामिल हैं। ये दोनों भव्य-विशाल मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित हैं।

राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सनातन संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया। तब चोल वंश की नौसेना बहुत उन्नत और शक्तिशाली थी। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका, मालदीव, मलयेशिया, थाईलैंड तक विजयी सैन्य अभियान किए। चोल राजवंश की छाप चीन तक भी थी। अपने संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु राजेंद्र प्रथम ने विशेष राजनीयक दूत चीन भेजे। बीते कई दशकों में तंजावुर, तिरुवरूर और पुडुकोट्टई में प्राचीन चीनी सिक्के मिले हैं, जो भारत-चीन के बीच व्यापारिक-वाणिज्यिक संबंधों के साथ चोल की कूटनीतिक दक्षता और सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। चोल साम्राज्य के सत्ता हस्तांतरण का चिह्न 'सेंगोल'-जिसे राजदंड भी कहा जाता है-मई 2023 से नवनिर्मित संसद भवन में न्याय और निष्पक्ष शासन के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठापित है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक भारतीय नेतृत्व का ब्रितानी छलकपट की जंजीरों से शीघ्र मुक्त होना अपेक्षित था। परंतु विडंबना यह रही कि राष्ट्र-पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व जिन हाथों में सौंपा गया, उनका एक बड़ा वर्ग उस औपनिवेशिक शिक्षा (1835-36) की उपज था, जिनमें भारतीयों को बौद्धिक तौर पर अंग्रेज बनाना अंतिम लक्ष्य था। तत्कालीन सत्तातंत्र के सानिध्य से शिक्षा-जगत और अन्य निर्णायक संस्थानों पर ये लोग काबिज हुए, जिनका लक्ष्य भारतीयों को उनकी संस्कृति की जड़ों को काटना था और जो कृत्रिम पाकिस्तान के जन्म में सहभागी भी रहे थे-उन्होंने औपनिवेशिक नैरेटिव को 'सेकुलरवाद' की आड़ में और अधिक व्यापकता प्रदान की।

'द्रविड़ आंदोलन' की उत्पत्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में वर्ष 1813 में जोड़े गए उस विवादास्पद अनुच्छेद की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने ब्रिटिश पादरियों और ईसाई मिशनरियों को स्थानीय भारतीयों के धर्मांतरण का मार्ग प्रदान किया। इसी सांठगांठ के अंतर्गत, वह संगठित अभियान तैयार हुआ, जिसकी नींव 16वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसिस जेवियर ने रखी थी, जो धर्मांतरण अभियान में ब्राह्मणों को सबसे बड़ा अवरोध मानते थे। तब कालांतर में ईसाई मिशनरियों और चर्च के प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन से वर्ष 1916-17 में 'साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन'-जिसे 'जस्टिस पार्टी' या 'द्रविड़ कड़गम' (डीके) के नाम से भी जाना गया-उसका गठन किया गया।

इसमें इरोड रामासामी नायकर प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने न केवल 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता पर शोक व्यक्त किया, अपने जहरीले अभियानों में खुलेआम हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को जूते-चप्पल की माला पहनाकर जुलूस निकालना शुरू कर दिया। तमिलनाडु की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके उसी की राजनीतिक उपज है, जिसके शीर्ष नेता आज भी खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग करके सनातन संस्कृति को मिटाने का दम भरते हैं। विडंबना यह है कि जिन अपमानजनक जुमलों का प्रयोग एक शताब्दी पूर्व डीके के तत्कालीन नेता कांग्रेस के लिए करते थे, वे जुमले अब कांग्रेस के समर्थन से भाजपा-संघ के लिए आरक्षित हो चुके हैं।

यक्ष प्रश्न यह है कि तमिल संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का वास्तविक ध्वजवाहक कौन है? जिन्होंने सनातन संस्कृति के प्रति घृणा का प्रचार-प्रसार किया और उसी विचारधारा से प्रेरित ये नेता जो अब भी वही विषवमन कर रहे हैं; या फिर वे महान सूर्यवंशी चोल सम्राट, जिन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया?

edit@amarujala.com

जीवन धारा

वर्जीनिया वुल्फ

खुशी की तलाश हर किसी की यात्रा का हिस्सा है। आखिर खुशी क्या है? क्या वह बाहर की चीजों, पैसा, प्रसिद्धि या प्रशंसा में है? नहीं। खुशी हमारे मन की आजादी में है। वह उस पल में है, जब हम छोटे-छोटे काम में दिल से जुड़ते हैं।

जीवन को बहुत गंभीरता से न लें

जीवन का अर्थ क्या है? यह सवाल मेरे मन में बार-बार उठता है, जैसे कोई लहर किनारे से टकराकर फिर लौट आती है। जीवन कोई निश्चित रास्ता नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा है, कभी शांत, कभी तूफानी। मेरे लिए, जीवन उन छोटे-छोटे पलों में बसता है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर सांस, हर विचार, हर मुलाकात, ये सब जीवन के रंग हैं। छोटे पल जीवन को गहराई देते हैं।

जीवन को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। खुद को समझे बिना दुनिया को समझना असंभव है। हम अक्सर भागते हैं, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपनी सच्चाई से। लेकिन थोड़ा ठहर जाएं। अपने मन की गहराइयों में उतरें। वहां हमें जवाब मिलेंगे। मैंने अपने जीवन में कई बार अंधेरे का सामना किया, लेकिन हर बार मैंने पाया कि वह अंधेरा मुझे मेरे बारे में कुछ नया सिखाता है। अपने दुख को गले लगाओ, क्योंकि वह हमें और मजबूत बनाएगा। जीवन में खुशी की तलाश हर किसी की यात्रा का हिस्सा है। आखिर खुशी क्या है? क्या वह बाहर की चीजों में है, पैसा, प्रसिद्धि, या प्रशंसा? नहीं। खुशी हमारे मन की आजादी में है। वह उस पल में है, जब हम छोटे-छोटे काम में दिल से जुड़ जाते हैं। जैसे किताब पढ़ते समय उसमें खो जाना हो, जब हम किसी से दिल से बात करते हैं, या जब हम अकेले में अपने विचारों के साथ नाचते हैं। और जैसे कोई बच्चा नदी के किनारे कंकड़ फेंकता है, वह उसके लिए अपार खुशी है। स्वयं के भीतर झांके और अपनी खुशी ढूंढें, और उसे थाम लें। लेकिन जीवन सिर्फ खुशी नहीं है। यह दुख, असमंजस और अनिश्चितता से भी बना है। जीवन एक दिन में कितना कुछ समेटे होता है। एक ही दिन में हम हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं और कभी-कभी खो जाते हैं।

जीवन कितना अजीब है, कितना जटिल। इसे सरल बनाने की कोशिश न करें। इसकी जटिलता को स्वीकार करें। हर इन्सान, हर कहानी, हर पल एक नया सबक लाता है। हमें बस उसे सुनने की जरूरत है। अपने आप को व्यक्त करना सीखें। वह जगह, वह समय, जहां हम अपने आप को पूरी तरह आजाद महसूस करते हैं? उसे बनाएं। अपनी कहानी लिखें, चाहे वह कागज पर हो, या हमारे काम में, या हमारे रिश्तों में। जीवन में दूसरों के साथ जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। मैंने हमेशा महसूस किया कि लोग एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दुनिया और खूबसूरत हो सकती है। लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने में कुछ जादू है। अपने दोस्तों, परिवार, या अनजान लोगों के साथ समय बिताएं। जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। यह कठिन है। यह कभी-कभी दुख देता है। लेकिन यह सुंदर भी है। हर पल को, हर अनुभव को जीना सीखें। हर दिन एक नया मौका है। हर सूरज की किरण, हर हवा का झोंका, हमें बुलाता है। उसका जवाब दें। नाचें, गाएं, लिखें और प्यार करें। जीवन एक किताब है और हम इसके लेखक हैं। अपने जीवन को पूरे दिल से और पूरी आजादी से जिएं।

छोटे-छोटे पलों को महसूस करें

जीवन कोई फिल्म की स्क्रिप्ट भर नहीं है, जहां कैमरा सिर्फ बड़े किरदार और उसकी बेहतरीन जीवनशैली पर फोकस कराता है। जीवन फिल्म में मौजूद हर छोटे किरदार से बना है, जहां खुशी, गम और आंसू सब कुछ हैं। इन सबका अपना अनोखा अर्थ भी है। हम जीवन के हर पल को तभी खुलकर जी पाएंगे, जब छोटे-छोटे पलों को महसूस करेंगे।

सूभ

दूसरा पहलू

हम हाथ धोने से लेकर अन्य वस्तुओं को खूब साफ करते हैं, पर सबसे ज्यादा छुए जाने वाले फोन को लेकर लापरवाह हैं।

अंतिम बार कब साफ किया था अपना फोन

हम अपने हाथ धोते हैं, शॉपिंग ट्रॉलियों को सैनिटाइज करते हैं और कैफे टेबल को साफ करते हैं, लेकिन हमारे फोन का क्या? हम इस उपकरण को दिन में दर्जनों बार छूते हैं और किचन से लेकर ड्राइविंग टेबल हर कहीं लेकर जाते हैं, यहां तक कि बाथरूम में भी। फोन कई तरह के कीटाणुओं से दूषित हो सकते हैं। ऐसे में, आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आपने अंतिम बार अपना फोन कब और किससे साफ किया था? अगर आप गलत तरीके से फोन को साफ करते हैं, तो आपके फोन की रक्षात्मक परत, वाटरप्रूफ सीलें और कई संवेदनशील बिंदु प्रभावित हो सकते हैं। टचस्क्रीन पर अंगुलियों के निशान और धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए स्क्रीन को पोंछना सुंदरता और फोन पर काम करने की सुविधा की दृष्टि से भी जरूरी है। हालांकि ऐसा करने की स्वास्थ्य से जुड़ी वजहें भी हैं।

मीना झा

मोबाइल फोन को जब भी जांच की जाती है, तो निस्संदेह बैक्टीरिया और वायरस की सैकड़ों प्रजातियां मिलेंगी। ये सभी प्रजातियां बीमारी का कारण न भी हों, पर संक्रमण तो फैला ही सकती हैं। हम बाथरूम में फोन का उपयोग करते हैं और फिर उसे अपने मुंह के पास रखते हैं। खाना खाते समय उसे छूते हैं। बेडरूमों, कैफे, पार्टियों व कॉलेज की कक्षाओं में भी हम खुद तो मोबाइल का उपयोग करते ही हैं, यह दूसरों के हाथों से भी गुजरता है। हम हाथों को दिन में कई बार धोते हैं, पर फोन को शायद ही कभी साफ करते हैं। जो फोन साफ करते भी हैं या उसे सैनिटाइज करते रहना चाहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा करते हुए वे फोन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। एप्पल और सैमसंग, दोनों ही अपने डिवाइस पर ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिरका, एरोसोल स्प्रे, विंडो क्लीनर या उच्च सांद्रता वाले अल्कोहल वाइप्स (70% से ज्यादा) का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन एक ओलिएफोबिक परत से ढके होते हैं-एक पतली परत, जो अंगुलियों के निशान और धब्बों को रोकने में मदद करती है। फिर फोन को कैसे साफ करें? ज्यादातर तकनीकी कंपनियां स्क्रीन क्लिन व चार्जिंग पोर्ट जैसे नाजुक हिस्सों को साफ करने के लिए 70 फीसदी आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाइप्स (इससे ज्यादा नहीं), मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े और नायलॉन या एंटी-स्टैटिक मुलायम ब्रिस्टल वाले ब्रश इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। फोन को कठोर चीजों से और बार-बार साफ करने से भी बचें। फोन को दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है। बाथरूम में ले जाने या अन्य जोखिम भरी जगहों पर ले जाने पर इसे जरूर साफ करना चाहिए।

-द कन्वर्सेशन से

मोबाइल फोन की जब भी जांच की जाती है, तो निस्संदेह बैक्टीरिया और वायरस की सैकड़ों प्रजातियां मिलेंगी। ये सभी प्रजातियां बीमारी का कारण न भी हों, पर संक्रमण तो फैला ही सकती हैं।

गलत तरीके से साफ करने पर फोन की रक्षात्मक परत, वाटरप्रूफ सीलें और कई संवेदनशील बिंदु प्रभावित हो सकते हैं।

आंकड़े

डॉक्टरों के इस्तीफे

देश के बीस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) से वर्ष 2022 से 2024 के बीच 429 डॉक्टरों ने विभिन्न कारणों से इस्तीफा दिया है।

नई दिल्ली	52
ऋषिकेश	38
रायपुर	35
बिलासपुर	32
मंगलागिरी	30

आंकड़े इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों के मामले में शीर्ष संस्थानों के | स्रोत : MoHFW

एकनाथ जी महाराज की कथा का वेश्या पर इतना प्रभाव हुआ कि उसे अपने कर्मों से घृणा होने लगी। बाद में महाराज ने उसे 'राम कृष्ण हरि' जपने के लिए कहा।

जपो राम-कृष्ण हरि

पैठण में रहने वाली एक वेश्या चतुर, सुंदर और नृत्य आदि में कुशल थी। उसके पूर्व जन्म व ईश्वर कृपा का ही सुफल था कि वह कभी-कभी एकनाथ महाराज के कीर्तन सुनने के लिए जाया करती थी। एक दिन एकनाथ महाराज ने भागवत को पिंगलाख्यान कहा। उसे सुनकर तो उस वेश्या की चित्तवृत्ति ही सुधर गई।

वह पश्चाताप करने लगी, 'मैं कैसी अभागिन हूं, जो चमड़े से घिरे विष्ठा-मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अपना जीवन बिता रही थी। हृदयस्थ अक्षय आनंद का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ।' उसे अपने कर्मों से घृणा होने लगी और खुद को घर में बंद कर लिया। वह एकनाथ जी का स्मरण करने लगी और सोचती थी कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। इसे संयोग कहें या एकनाथ जी महाराज की कोई लीला, एक दिन वह गोदावरी में स्नान करके उसी रास्ते से निकले, जिस रास्ते में वेश्या का घर था। उसने घर के झरोखे से महाराज को देखा, तो दरवाजा खोलकर दौड़ी हुई आई और गद्गद कंठ से बोली-महाराज! क्या इस पापिन के घर को आपके चरण पवित्र कर सकते हैं? बताते हैं कि एकनाथ जी जब अंदर गए, तो वेश्या का घर प्रकाशित हो उठा। उन्होंने उसे, 'राम कृष्ण हरि' मंत्र जपने के लिए कहा। बताते हैं कि करीब दस वर्ष तक वेश्या ने एकनाथ जी महाराज से मिले गुरुमंत्र का निरंतर जप किया और श्रीकृष्ण के स्वरूप को ध्यान में देखते हुए अपना भौतिक चोला छोड़ दिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 18 अगस्त, 1950

कांग्रेस का ढांचा न बदला तो वह नष्ट हो जाएगी

देश गुलाम हो जायगा
नाजिक अविशेशन में चेत जाओ!

कांग्रेस पंचायत के 950 प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कांग्रेस का वर्तमान ढांचा न बदला गया और कांग्रेसियों ने उदासीनता से काम लिया, तो एक दिन यह पार्टी नष्ट हो जाएगी।

फास्टैग में पैसे फंसे न रह जाएं

एक साल में औसतन 25 लाख पुराने वाहन बेचे या स्क्रैप किए जाते हैं। प्रति वाहन 300 रुपये के हिसाब से करीब 750 करोड़ रुपये फास्टैग में फंसते हैं।

सुभाष चंद्र कुशवाहा | **मुद्दा**

फास्टैग खातों में फंसी धनराशि का मुद्दा एक गंभीर वित्तीय चिंता का विषय बन रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ताओं के फास्टैग खातों में करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं, जो बैंकों द्वारा स्वच्छंदित रूप से हस्तांतरित नहीं किए जा रहे हैं।

फास्टैग, एक डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली को 2021 में अनिवार्य कर दिया गया, जिसके कारण सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग लगवाना अनिवार्य हो गया, चाहे वे टोल मार्ग पर जाएं या नहीं। यह नीति अपने आप में उन महिलाओं और बुजुर्ग उपभोक्ताओं के विरुद्ध है, जो केवल शहरी क्षेत्रों में वाहन चलाते हैं। कई बार वाहन की अवधि पूरा हो जाने के बाद जब उन्हें कबाड़ी को बेचा या कटवाया जाता है, तब भी उस वाहन के फास्टैग में कुछ न कुछ राशि शेष रहती है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 20 लाख पुराने वाहन बेचे जाते हैं, और लगभग पांच से सात लाख वाहन स्क्रैप किए जाते हैं (वाहन स्क्रैप नीति 2021 के अनुसार)।

प्रत्येक फास्टैग खाते में औसतन 200-500 रुपये की अवशिष्ट धनराशि रहती है। यह राशि न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता और उपयोगकर्ता द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त फंड्स पर आधारित है। यदि प्रति वर्ष 25 लाख वाहन (बिक्री और स्क्रैप) प्रभावित होते हैं और औसतन 300 रुपये प्रति फास्टैग फंसता है, तो कुल फंसी धनराशि अनुमानित 750 करोड़ रुपये हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण, उपभोक्ता अक्सर फास्टैग-खाता बंद करने की प्रक्रिया से गुजरते नहीं हैं, जिससे उनकी धनराशि फंसने की आशंका बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्रों में, जहां वाहन बिक्री अधिक होती है, प्रक्रियात्मक देरी और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता के कारण भी धनराशि फंसी रहती है।

वाहनों को बेचने और स्वामित्व परिवर्तन कराने की वजह से भी पुराने स्वामी के फास्टैग में अवशेष राशि रह जाती है। इस प्रकार लाखों उपभोक्ताओं के खातों में जमा अवशेष राशि या तो गलत तरीके से डेबिट हो रही है या ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के विगत कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 120, 2022 में 320 और 2023 में 500 करोड़ से ज्यादा की अवशेष राशि अनुचित तरीके से फंसी पड़ी थी। अगर हम 2022-23 की वृद्धि दर के अनुसार अनुमान लगाएं, तो 1.2 करोड़ निष्क्रिय फास्टैग खातों में 2024 तक कुल 830 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अनुचित तरीके से रोकी पाई जा सकती है।

फास्टैग में उपभोक्ताओं के पैसे फंसे होने के दूसरे कारण भी हैं, जैसे कि टोल प्लाजा पर गलत डेबिट होना या बंद खातों में पैसा ट्रांसफर न होना। फास्टैग नियमों के अनुसार, निष्क्रिय खातों (छह महीने तक इस्तेमाल न होने पर) की राशि सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। इस नियम का दुरुपयोग करने के लिए बैंकों द्वारा लापरवाही बरती जाती है और उपभोक्ताओं द्वारा समय पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, रिफंड प्रक्रिया में छह से आठ महीने की देरी कर दी जाती है और तब अवशेष धनराशि वापस नहीं हो पाती। आरबीआई के नियम 10(2) के अनुसार, ऐसे निष्क्रिय खातों की राशि को 'अनर्जित आय' मानकर सरकारी कोष में जमा किया जा सकता है।

अपने देश में 2024 तक लगभग 6.8 करोड़ फास्टैग खाते सक्रिय थे, जिनमें 85 प्रतिशत निजी वाहनों (कार) और 15 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक/बस) के थे। ये आंकड़े प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। इसलिए उपभोक्ताओं के हित में यह जरूरी है कि फास्टैग की धनराशि को दूसरे फास्टैग या बैंक खाते में ट्रांसफर की स्वचालित सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो वाहन बिक्री या स्क्रैप होने पर अवशिष्ट धनराशि को उपयोगकर्ता के बैंक खाते या नए फास्टैग खाते में स्थानांतरित कर सके। वाहन पंजीकरण डाटाबेस (VAHAN) के साथ फास्टैग सिस्टम को एकीकृत करके भी स्वामित्व हस्तांतरण की जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट की जा सकती है।

बैंकों और फास्टैग प्रदाताओं को खाता बंद करने और रिफंड की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक-क्लिक रिफंड सुविधा शुरू की जा सकती है। भारत की वाहन स्क्रैप नीति (2021) के तहत स्क्रैप सेंटरों को फास्टैग खाता बंद करने या धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करना चाहिए। स्क्रैप सेंटर को VAHAN डाटाबेस के माध्यम से एनपीसीआई को सूचित करना चाहिए, ताकि फास्टैग स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो और अवशिष्ट धनराशि रिफंड हो। आखिर हम जब उपभोक्ताओं से सड़क प्रयोग हेतु कर वसूल रहे हैं, तो उनके हितों का भी ख्याल रखें।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 18 अगस्त 2025

यह तो होता रहा है...

डॉनल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अधर में लटक गई है। यह अनिश्चितता दोनों में से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। हालांकि अलास्का समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति ट्रंप का नरम रवैया थोड़ी उम्मीद जरूर जगाता है।

असमंजस की स्थिति । ट्रेड डील के लिए अमेरिकी अधिकारियों को इसी 25 तारीख को भारत आना था, लेकिन मौखिक तौर पर बताया गया कि अब यह विजिट नहीं होगी। अभी तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे असमंजस बढ़ गया है। पहले माना जा रहा था कि अगस्त आखिर या सितंबर तक दोनों देश एक मिनी डील तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए दोनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब सबकुछ बिल्कुल थम जाना द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सही नहीं।

US संग ट्रेड डील रुकी

संबंधों को नुकसान । व्यापारिक समझौते में क्यों अड़चन आ रही है, इस बारे में अब सभी को पता है, लेकिन भारत की चिंताओं को समझने और बातचीत के जरिये समाधान निकालने के बजाय ट्रंप दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। मौजूदा संकट इसलिए भी ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए भारत को अहम साझेदार मानने के बावजूद अमेरिका आपसी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठा रहा है। हालांकि इतिहास पर नजर डालें, तो वॉशिंगटन के लिए यह नई बात नहीं लगती।

पुरानी आदत । 80 के दशक के आखिर में भी अमेरिका को व्यापार घाटे की चिंता सता रही थी और तब उसके निशाने पर जापान था। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला कि अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ अनुचित व्यापार नीतियां अपनाता है, तो उस पर टैरिफ लगाया जा सके। लेकिन, यह अधिकार मिलने के बाद तत्कालीन US प्रेजिडेंट जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश ने जापान के साथ-साथ भारत और अमेरिकी सहयोगियों - यूरोप, दक्षिण कोरिया व ताइवान पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लाद दिया। 1989 में जब उन्होंने भारत को टारगेट किया था, तब भी सरकार का यही कहना था कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेगी।

इतिहास से सबक । अमेरिका फिर से इतिहास को दोहरा रहा है। ट्रंप चीन को सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, लेकिन सबसे पहले समझौता उसी से किया। वहीं यूरोपीय संघ (EU) और भारत जैसे सहयोगियों के प्रति उनका रुख ज्यादा अड़ियल है। EU ने भले डील कर ली हो, पर उसके कई सदस्य देश इससे खुश नहीं हैं। ऐसे में भारत को ट्रंप प्रशासन से बात करते हुए अमेरिका के अतीत और आज के हालात, दोनों पर नजर रखनी होगी। यह डील अमेरिकी इकॉनमी के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जितनी भारत के लिए।

चक्र-व्यू

थैंक्यू चीन

राहुल पाण्डेय

इन दिनों मेरा लैपटॉप खराब है। मजबूरन बहुत सी चीजें कागज पर हाथ से लिखनी पड़ रही हैं। बहुतों के यह कहने के बावजूद कि चीनियों का माल मत खरीदो, मैंने लैपटॉप खरीद लिया था। बेचारा छह महीने में ही लुप-लुप करके बैठ गया। मगर हाथ की लिखाई के मामले में मैं चीनियों का शुक्रगुजार हूं कि माल खराब होते ही वो हमें इतिहास में पटक देते हैं। एक वक्त था, जब हम सभी हाथ से ही लिखते थे। जिसकी हैंडराइटिंग खराब होती, उसे पहले मम्मियां सुधारती थीं, फिर स्कूल में मैम। जिसकी अच्छी होती थी, उसे इतनी वाहवाही मिलती कि बाकी बैठकर जलते-फुंकते! मेरी मां मेरे लिखे को चिड़िया की टांग कहतीं। रिपोर्टिंग के दौरान जल्दी-जल्दी सब कुछ लिख लेने की मजबूरी ने इसे कभी चिड़िया की मोती जैसी आंख न बनने दिया। लेकिन कभी कभी मन करता है शब्दों को खूब बना के लिखने का। लिखें तो लगे मोती सहेज रहे हों। कोई हीरा, कोई पन्ना, कोई मूंगा तो कोई पुखराज। शब्द नग ही तो हैं। सही जगह सज गए तो सुभान अल्लाह, नहीं तो खैर सल्लाह!

और नहीं तो लगभग नब्बे के पूरे ही दशक तक मन ही नहीं, तन और धन की भी लिखाई हाथ के ही हिस्से आती रही। क्या कविता, क्या कोष, हर किसी का हिसाब हाथ के ही हवाले रहा। क्या पोस्टकार्ड यानी SMS, और क्या अंतर्देशीय यानी ईमेल- सब हाथ के हवाले। किताब तो बहुत बाद में छपीं, पहले वे कागज पर हाथ से उतारी गईं। किसी कवि ने कभी कहा था, 'पूछती हैं स्त्रियां, क्या तुमने भी मेरी तरह सीने से लगाया होगा मेरा खत? स्याही के अलावा क्या पाया तुमने?' अब बेचारे कवि की हिम्मत नहीं कि ऐसी लाइनें लिख दे। स्याही के लिए पेन चाहिए होती है। पेन को ये लिखने वाला हाथ। लिखे हुए को चाहिए एक पाठक। पहले एक चिट्ठी आती थी। गली भर के लोग लिखावट के जरिए उसमें पलटी मन की करवटें गिन लेते थे। तकनीक ने हमारी लिखाई तो रखी, लिखावट बिसरा दी थी। वो तो शुक्र है चीन का, कि इतने दिनों बाद मुझे फिर से कागज से दो-दो हाथ करने का अवसर दिया। वरना मन की करवट गिनने का मौका जल्दी कहां मिलता है?

एकदा

फूलों की ख़ुशबू

थियोसॉफिकल सोसायटी की स्थापना सन 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके संस्थापकों में से एक थीं रूसी मूल की दार्शनिक हेलेना पेत्रोवना ब्लावत्स्की। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक खोज और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह हमेशा यात्राओं पर रहतीं और जहां जातीं, वहां लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करतीं। एक बार सफर के दौरान वह बार-बार अपनी झोली से कुछ निकालकर खिड़की से बाहर फेंक रही थीं। यह देखकर दूसरे यात्री हैरान हो गए और पूछ बैठे, 'आपने झोली में क्या रखा है और बार-बार बाहर क्या फेंक रही हैं?' ब्लावत्स्की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 'ये फूलों के बीज हैं। बारिश के बाद ये खेतों, झाड़ियों और पटरियों के किनारे उगेंगे और सुंदर फूल बनकर खिलेंगे।' एक यात्री ने उत्सुकता से पूछा, 'लेकिन ऐसा करने से आपका क्या फायदा होगा? क्या आप इन फूलों को दोबारा देखने यहां आएंगी?' ब्लावत्स्की ने सहज भाव से कहा, 'शायद नहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगनिगत लोग इन फूलों को देखेंगे, उनकी खुशबू और सुंदरता का आनंद उठाएंगे। आज मैं जिन फूलों से खुशबू हूं, वे भी किसी और ने लगाए थे। वैसे ही कल कोई मेरे लगाए फूलों से खुश होगा।' उनकी यह बात मानवीय प्रेम, उदारता और निस्वार्थ प्रेरणा की अनूठी मिसाल है।

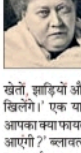

संकलन : **दिलीप लाल**

पूतिन और ट्रंप की भेंट से यूक्रेन युद्ध के रुकने का रास्ता तो खुला, लेकिन पता नहीं इसमें कितना समय लगेगा

अलास्का से पूरी नहीं हुई भारत की आशा

चंद्रभूषण

अलास्का के ऐंकरेज शहर में अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपतियों की मुलाकात से सार्वजनिक स्तर पर कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया है। डॉनल्ड ट्रंप ने वापसी की यात्रा में बताया, 'एक खास डील के बिना कोई और डील नहीं।' खास डील, यानी यूक्रेन में शांति की स्थापना। ट्रंप जानते हैं और बाकी दुनिया भी जानती है कि एक दिन में बंदूकें खामोश करवा देने वाली बात चुनाव प्रचार के लिए ही ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई रोकना टेढ़ा काम है। लेकिन पूतिन से उनका मिलना संवाद के लिए एक रास्ता खोलने वाला जरूर साबित हुआ है।

रूस का पलड़ा भारी । साढ़े तीन साल से ज्यादा लंबी चल चुकी लड़ाई में कुछ महीनों से पलड़ा रूस का ही भारी दिख रहा है। शायद यह दिखाने के लिए कि मामला उतना एकतरफा भी नहीं है, ऐन बातचीत के दिन ही यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन्स से सुदूर कैस्पियन सागर में खड़े एक रूसी मालवाहक जहाज पर हमला किया। लड़ाई में इससे चाहे जितना भी फायदा उसे हुआ हो, बैठक में यूरोपीय देशों को शांति के रास्ते में रोड़े अटकाने वाली शक्ति बताने का एक मौका पूतिन को जरूर मिल गया।

यूरोप का विरोध । पूतिन को अलग-थलग करने की यूरोपीय कोशिशें अलास्का में रेड कार्पेट पर चलकर डॉनल्ड ट्रंप से उनके हाथ मिला लेने के साथ ही ध्वस्त हो गई हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से यह पहला मौका है, जब अमेरिका से तो रूस के रिश्ते दोस्ताना दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि यूरोप ने उसके खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। छवि के स्तर पर यह इतना प्रबल संकेत है कि वार्ता के तुरंत बाद यूरोप के सभी बड़े नेताओं को डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रीफ किए जाने के बावजूद वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिका पहुंचकर उनसे आमने-सामने मुलाकात के लिए पहली संभव तारीख लेनी पड़ी।

यूक्रेन का हाल । यूरोप के नेताओं को आज भी लगता है कि अपने हथियारों और कूटनीति के बल पर वे रूस के खिलाफ इतना मजबूत दबाव बना सकते हैं कि पूतिन तत्काल लड़ाई रोकने और यूक्रेन से अपनी फौजें हटाने को मजबूर हो जाएं। अभी की स्थिति में यह किसी दिवास्वप्न जैसा ही लगता है। 2024 के अमेरिकी आम चुनाव में और कई यूरोपीय देशों के चुनावों में भी यूक्रेन के उग्र समर्थक नेताओं की पराजय के बाद से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। सौदेबाजी की आखिरी कोशिश की तरह यूक्रेनी फौजों को रूस के कुस्क प्रांत का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लेने को राजी किया गया। लेकिन यह कब्जा हटाने के लिए ऐन मौके पर उत्तर कोरिया की मदद लेकर रूस ने बाजी पलट दी। उसके बाद से यूक्रेन का हर दांव उलटा पड़ रहा है और यूरोप की भी बार-बार मद पिटती जा रही है।

रूस-अमेरिका के रिश्ते सुधरे

- साढ़े तीन साल से चल रहे युद्ध में रूस का पलड़ा भारी
- यूक्रेन के साथी यूरोपीय देश अभी कमजोर पड़े हुए हैं
- भारत से अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने के संकेत नहीं

जेलेंस्की की चाहत । पूर्वी यूक्रेन के जिस हिस्से में अभी सबसे घनघोर लड़ाई चल रही है, उसे फोर्ट्रेस बेल्ट यानी किलेबंदी का इलाका कहा जाता रहा है। इस ठंडे इलाके में आमने-सामने की जंग सितंबर या हद से हद अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक ही चल पाती है। उसके बाद चार महीना पूरा इलाका बर्फ में जमा रहता है, और बात सुरक्षित जगहों से एक-दूसरे पर ड्रोन या मिसाइल फेंकने तक सिमट जाती है। अभी रूसी फौजें किलेबंदी वाले यूक्रेन के आधे से ज्यादा शहरों पर या तो कब्जा कर चुकी हैं, या तीन तरफ से उन्हें अपने घेरे में ले चुकी हैं। जेलेंस्की की कोशिश फिलहाल यही होगी कि युद्धबंदी अगर होनी है तो जल्द से जल्द हो जाए। ऐसा न हो पाया और लड़ाई अभी जैसी ही एकतरफा शक्ल में अगले डेढ़-दो महीने और खिंच गई तो रणनीतिक महत्व के कई शहर उनके हाथ से निकल जाएंगे और जाड़े शुरू होने के साथ सौदेबाजी की उनकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी।

ट्रंप को टक्कर नहीं । डॉनल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति एक मायने में बहुत उत्तम है कि उनकी अथॉरिटी को चुनौती देने वाला अभी कोई नहीं है। पिछले कार्यकाल में उन्हें चुनौती या तो यूरोपीय नेताओं की ओर से मिली थी, या चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की तरफ से। चीन ने इस बार अपने हितों की एक रेखा खींच दी है और ट्रंप के रास्ते में ज्यादा न ही पड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि यूरोप के किसी नेता में बराबरी की टक्कर देने वाला कद ही नहीं बचा है।

भारत की आशा । खास तौर पर भारत की नजरें ट्रंप-पूतिन वार्ता पर इसलिए लगी हुई थीं कि रूस पर दबाव डालने के लिए सेकंडरी टैरिफ की जो तलवार उससे व्यापार करने वाले देशों के सिर पर अमेरिका की ओर से लटका दी गई है, उसे हटाने का शायद कोई रास्ता निकल आए। ट्रंप ने न तो पूतिन से बातचीत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, न ही अलास्का से वापसी के बाद दिए गए बयानों में अपनी धमकी से पीछे हटने का कोई संकेत दिया है। जितना बड़ा भूगोल रूस के हिस्से में आता है, छोटा से बड़ा तक संसार का एक भी देश ऐसा नहीं है, जो किसी न किसी चीज के लिए रूस पर निर्भर न करता हो। लेकिन उसी रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका बहुत जल्द 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात कर भारत पर लगाने जा रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रॉडक्ट ही नहीं, ख़ुशियां भी बेचते हैं विज्ञापन

जब 'Skip' का ऑप्शन नहीं था, तब बड़ी बेचैनी होती थी विज्ञापन देखकर। ऐसा लगता कि किसी ने गहरी नींद से जगा दिया हो - किसी कहानी में उतराते मन को अचानक से कोई एड हाथ पकड़ कर किनारे खींच लाता - पूरी रिदम ही टूट जाती थी। लेकिन, अपने एक एपिसोड में अखबार पढ़ते हुए महान सत्य अन्वेषी (यानी जासूस) व्योमकेश बक्शी ने कहा कि असली खबर तो विज्ञापनों में होती है! दुनिया के बाजार में क्या नया चल रहा है, यह जानना हो, तो देखिए विज्ञापन!

वैसे जिसे जरूरत है, वह कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेगा और बेचने वाला बेच ही लेगा। लेकिन, जब कुछ बनाने का हुनर आया, तो उसी के साथ बेचने की भी कला आ गई इंसानों में और तभी से विज्ञापन भी चल निकले, रूप जरूर दूसरा रहा। प्राचीन मिस्र से लेकर ग्रीस, रोम और भारत तक - किसी न किसी तौर पर मौजूद रहा विज्ञापन। थियेटर या ग्लैडिएटर फाइट शो की जानकारी लिखी जाती थी पुराने शहर की दीवारों पर - भारत में व्यापारी ऊंची आवाज में हांक लगाकर गुणगान करते अपने सामानों का। दीवारों से सरकते-सरकते वही विज्ञापन आ गया न्यूजपेपर, मैगजीन और स्क्रीन पर।

एड जितनी जरूरत हैं व्यापारी की, उतने ही जरूरी हैं ग्राहक के लिए भी। अच्छे विज्ञापन सिर्फ प्रॉडक्ट नहीं बेचते। वे कहानियां सुनाते हैं - किसी बच्चे का रूठ जाना और जलेबी पर मान जाना, एक आम परिवार में आई पहली कार, बारिश में चाय की दुकान पर दोस्तों का जमघट या पुराने घर का नए रंगों में रंगकर बातें करना। कई बार ये छोटी-छोटी कहानियां जीवन से जुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी पहचान हो इनसे।

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

एक नजर, बस इतनी ही मांग रहती है विज्ञापन की हमसे। बहुत रचनात्मकता चाहिए इसके लिए। विज्ञापन देखने का आनंद इस बात में भी है कि ये क्रिएटिव लोगों की कल्पना की उड़ान दिखाते हैं। एक अच्छे एड में सब कुछ इतनी खूबसूरती से गढ़ा जाता है, जैसे कला का टुकड़ा। कई बार तो विज्ञापन जगह बना लेता है दिल में, जबकि उसके दाएं-बाएं का हिस्सा याद ही नहीं रहता। यानी असर छोड़ने के लिए थोड़ा वक्त भी बहुत है, बस असरदार होना पड़ेगा। विज्ञापन प्रासंगिक होते हैं और बेहद जिद्दी। वह सिखाते हैं कि समय के साथ ऐसे बदलते रहो कि कभी पुराने न पड़ो। न वे कभी हार मानते हैं और न शर्माते हैं। किसी ने पहले सेकंड में ही स्किप कर दिया तो क्या, किसी ने अखबार के पन्ने पर देखा तक नहीं तो क्या - अगली बार वे फिर आते हैं, फिर प्रयास करते हैं। इसी जिद ने बचाए रखा है उन्हें। जितना भरोसा उन्हें खुद पर होता है, उससे ज्यादा उस पर, जिसके लिए वे सिफारिश कर रहे होते हैं। भले हजार कमियां हो उसमें, पर वे बताते सिर्फ अच्छाई हैं। यही तो है एक अच्छे दोस्त की खासियत। तभी महान लेखक मार्क ट्वेन को कहना पड़ा कि कई छोटी और साधारण चीजें सही तरीके के विज्ञापन से बड़ी और महत्वपूर्ण दिखाई देने लगती हैं।

अच्छा विज्ञापन दिलों को छूता है। कुछ खरीदने के लिए नहीं कहता, फिर भी कुछ बेच जाता है। वह किसी सौदे के लिए हामी नहीं भराता, कुछ महसूस कराता है।

शेयर करें अपना अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesofindia .com और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

महाभारत मन में भी है, इससे लड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ

ब्रह्मा कुमारी शुक्ला

भारतीय संस्कृति में कहा जाता रहा है कि नर ऐसा आचरण करें, जो उन्हें नारायण बना दे और नारी ऐसा आचरण करें, जो उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा बनाए। यही आदर्श जीवन की दिशा और गंतव्य) दोनों तय करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, सृष्टि का आदि काल सतयुग था। इस सतयुगी संसार के प्रथम दैवी सम्राट श्रीनारायण थे, जिन्हें श्रीकृष्ण कहा जाता था। भारत को 33 कोटि देवी-देवताओं की भूमि माना गया है, जहां जन्म, कर्म और पूजा - तीनों पवित्र भाव से सम्पन्न होते हैं।

शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा एक है और वही समस्त आत्माओं का रूहानी पिता है, जबकि देवात्माएं अनेक हैं। सभी देवी-देवता भी जन्म-मृत्यु के चक्र में आते हैं, किंतु परमात्मा निराकार, अशरीरी और सदा विदेही है। वही सब आत्माओं के परम शिक्षक, सखा और सद्गुरु माने गए हैं।

कलियुग के अंतिम चरण में, जब अधर्म और विकार चरम पर पहुंच जाते हैं, तब परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अवतरित होते हैं और गीता ज्ञान व राजयोग की शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा मनुष्य आत्माओं को फिर से सतयुगी संस्कार और देवत्व का अधिकारी बनाती है। वास्तव में, श्रीनारायण और श्रीलक्ष्मी का संयुक्त स्वरूप ही विष्णु रूप माना गया है।

शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्मा को नई सृष्टि का पितामह कहा गया है। इसी से यह समझ में आता है कि महाभारत युद्ध का गूढ़ अर्थ केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक लड़ाई है। यानी महाभारत हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है। वासना, क्रोध, अहंकार और व्यसन जैसे शत्रु अपने-अपने अस्त्रों से हमारे ऊपर प्रहार करते रहते हैं। इन शत्रुओं से हम भाग नहीं सकते। इनसे जूझना ही सच्चा पुरुषार्थ है। इनसे जीत किसी हथियार से नहीं - आत्मज्ञान, परमात्मा की याद और पवित्र जीवनशैली से संभव है। यही साधना हमें सच्चा अर्जुन बनाती है, जो रूहानी शक्ति अर्जित कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है।

आज की परिस्थिति में भी यही संदेश प्रासंगिक है। समाज जिन संकटों और संघर्षों से गुजर रहा है, उनका समाधान बाहरी युद्ध से नहीं, आंतरिक परिवर्तन से संभव है। जब प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को हटाकर दिव्य गुणों को धारण करेगा, तभी संसार में शांति और समृद्धि संभव है। पौराणिक प्रसंग और कथाएं सांकेतिक रूप में हमें यही प्रेरणा देती हैं। कंस, जेल और कारागार विकारों और अभिमान के प्रतीक हैं, जबकि देवत्व और मुक्त जीवन उस अवस्था का प्रतीक, जब आत्मा परमात्मा के सान्निध्य में स्वतंत्र होकर जीती है। यही स्थायी आनंद और सच्चा वैभव है।

इसलिए हमें चाहिए सहज राजयोग का अभ्यास करें और अपने आचरण से सतयुगी आदर्शों को पुनर्जीवित करें।

अमीरों का खेल क्यों था क्रिकेट

मृत्युंजय राय

हाल ही में इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की तेंडुलकर-एंडरसन टेस्ट सीरीज के हर मुकाबले में स्टेडियम में भारी भीड़ जुटी। सीरीज इतनी रोमांचक थी कि आखिरी टेस्ट तक सस्पेंस बना रहा। 5वें मैच से पहले तक इंग्लैंड 2-1 से बढ़त बनाए हुए था। आखिरी मुकाबला जीतकर भारत ने 2-2 से सीरीज बराबर कर ली। बहरहाल, पूरी शृंखला के दौरान एक्सपर्ट्स टेस्ट मैच के भविष्य को लेकर भी चर्चा करते रहे। टेस्ट क्रिकेट 1877 से खेला जा रहा है और अगर इस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं तो वह इसी फॉर्मेट की वजह से। **Test Cricket: A History** नाम की किताब में टिम विगमोर इसी फॉर्मेट की रोमांचक दुनिया में ले जाते हैं। वह बताते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से नैतिकता और अच्छे व्यवहार से जोड़कर देखा जाता रहा है।

विचार विंडो

तेंडुलकर-एंडरसन सीरीज में भी भले ही दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों के बीच ग्राउंड पर गरमागरमी दिखी, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद जो रूट जैसे जेनरेशनल प्लेयर ने भारतीय बोलर मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की। ऋषभ पंत और वोक्स घायल होने के बावजूद जिस तरह से बैटिंग करने उतरे, उसने यह भी जाहिर कर दिया कि क्यों यह फॉर्मेट बनडे और T-20 के मुकाबले खिलाड़ियों का बहुत ही सख्त इम्तिहान लेता है।

टिम बताते हैं कि टेस्ट मैच को अगर खिलाड़ी के व्यवहार से जोड़कर देखा जाता है तो उसकी जड़ें विक्टोरियन इंग्लैंड में इसकी शुरुआत से जुड़ी हैं। पहले यह खेल अमीरों तक महदूद था। टेस्ट मैच कामकाजी दिनों की दोपहर में पांच दिन तक खेले जाते थे। इसलिए वर्किंग क्लास का इसमें शामिल होना मुमकिन नहीं था। टिम ने लिखा है कि कुछ लोग दिहाड़ी पर टेस्ट मैच खेला करते। ऐसे लोगों को तब महज खिलाड़ी माना जाता था, जेंटलमेन नहीं।

टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चिंता है पार्टिसिपेशन। जहां T-20 आज क्रिकेट को नए दर्शकों में ले जा रहा है, वहीं टेस्ट एक्सक्लूसिव क्लब बना हुआ है। इसमें सिर्फ 12 देश शामिल हैं। टेस्ट मैचों में भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं। क्लब में हाल में शामिल हुए अफगानिस्तान और आयरलैंड जैसे देशों ने बहुत मैच नहीं खेले। भारत-इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया जैसे इस खेल के दिग्गज देशों ने पिछले एक दशक में कहीं ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। इसकी वजह क्रिकेट इकॉनमी है। ये तीनों देश क्रिकेट के 'बिग थ्री' कहलाते हैं। इन देशों में सबसे अधिक फैन्स हैं। यहां क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग डील्स से असोसिएशंस को तगड़ी कमाई होती है। बाकी देश टेस्ट मैचों की मेजबानी से अच्छी कमाई नहीं कर पाते। उन्हें औसतन 5 लाख डॉलर का नुकसान हर सीरीज में उठाना पड़ता है। फिर, वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाड़ी तो टेस्ट मैच से बाहर रहकर प्रफेशनल T-20 लीग खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कमाई अधिक है।

हालांकि टेस्ट क्रिकेट को लेकर चिंता कोई नई बात नहीं। 1970 के दशक में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई, फिर आया T-20। लेकिन टेस्ट का जादू अब भी बना हुआ है। क्रिकेट में बड़ा खिलाड़ी उसी को माना जाता है, जिसने टेस्ट में भी खुद को साबित किया हो।

पीड़ितों से जानिए

प्रणव प्रियदर्शी

कथित मामूली और छोटे-मोटे अपराध भी विकिम को किस हद तक और कितने समय तक परेशान करते रहते हैं, इसका अंदाजा हमें नहीं होता। तभी हम उन अपराधों को छोटा-मोटा की श्रेणी में बनाए रखते हैं। मिसाल के तौर पर, स्टॉकिंग को लें तो पीड़ितों के अलावा शायद ही कोई इसे गंभीरता से लेता है। वजह भी है। यह ऐसा अपराध है, जिसमें शारीरिक संपर्क नहीं स्थापित होता न ही शरीर को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है, जख्मी होने या जान जाने का भी डर प्रायः नहीं रहता। शायद इन्हीं वजहों से इसकी शिकायत दर्ज कराना भी अक्सर गैरजरूरी माना लिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके यह सबसे ज्यादा घटित होने वाले अपराधों में शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि हर तीन में से एक महिला कभी न कभी इसका शिकार होती है। इसके परिणामों की बात करें तो हाल की एक हार्वर्ड स्टडी से पहली बार ये बात सामने आई है कि स्टॉकिंग का शिकार रही महिलाओं को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पत्रिका 'सर्कुलेशन' में पिछले दिनों प्रकाशित इस स्टडी के आंकड़े नर्सेज हेल्थ स्टडी -2 के तहत दो दशकों से निगरानी में रखे जा रहे समूह से लिए गए हैं। यह उन कुछेक लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रॉजेक्ट में है जिनका मकसद प्रमुख क्रॉनिक डिजीज के खतरों को समझना है। स्टडी के मुताबिक, जिन महिलाओं ने स्टॉकिंग की शिकायत दर्ज कराई उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क 41 फीसदी ज्यादा पाया गया। यही नहीं, जिन मामलों में महिलाओं ने प्रशासनिक आदेश हासिल कर लिया, उनमें यह खतरा 70 फीसदी तक बढ़ा हुआ पाया गया। जाहिर है, स्टॉकिंग जैसे अपराध शरीर पर घाव भले न करते हों, मन को घायल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। और हां, यह एक ऐसी चीज है जिसका सही इलाज समाज की संवेदनाओं को समूद्ध करने में है, पुलिसिया सुरक्षा तात्कालिक जरूरत भले हो, ठोस राहत नहीं साबित होती।

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ बेटियों को बढ़ने दें

16 अगस्त का लेख 'बेटी पढ़ी, फिर कहां गई' पढ़ा। यह लेख भारतीय समाज के सबसे बड़े विरोधाभास को उजागर करता है, जहां बेटियां शिक्षा में लड़कों से आगे हैं, वहीं कार्यक्षेत्र में उनकी भागीदारी लगातार घट रही है। यह स्थिति केवल सामाजिक सोच का परिणाम नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी है। शिक्षा को शादी तक सीमित करना और मातृत्व के बाद वापसी का अवसर न देना महिलाओं की क्षमता को दबा देता है। यह हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। चीन, अमेरिका, यहां तक कि सऊदी अरब तक हमसे आगे हैं। सवाल यह है कि जब हम बेटियों को पढ़ाने में इतना निवेश करते हैं, तो उन्हें अपने सपनों को जीने का पूरा अधिकार क्यों नहीं देते? अगर उन्हें पढ़ा-लिखाकर घर में रहने के लिए मजबूर करेंगे तो भारत महाशक्ति कैसे बन सकता है?

भास्कर गुप्ता, ईमेल से

■ अव्यावहारिक निर्देश

यह पत्र 13 अगस्त के संपादकीय 'तर्क के परे' से संबंधित है। नगर निकायों द्वारा स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी न कर पाना और रेबीज के खिलाफ उचित कार्रवाई न करना ही इस समस्या की जड़ है। स्ट्रे डॉग्स को उनके इलाकों से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना समस्या का समाधान नहीं। इसके लिए बजट की कमी तो है ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। सभी जानते हैं कि लाखों स्ट्रीट डॉग्स के लिए दो महीने में शेल्टर नहीं बनाए जा सकते और न ही उनके लिए जरूरी इंतजाम किए जा सकते हैं। SC के इस निर्देश पर व्यवहार में अमल मुश्किल है। बेहतर होगा इस पर दोबारा विचार किया जाए।

बाल गोविंद, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

भारत संग बातचीत के लिए नहीं आ रही अमेरिकी टीम - खबर
- पाकिस्तान को लोरी सुनाने वाले से उम्मीद ही क्या करे भारत!

कविता सैनी

बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (पूर्व में बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) के पंजीकृत कार्यालय: टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, नवाड़ा रोड, ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास, पालम, दिल्ली-110010 से मुद्रित। फोन: 011-23302202 फैक्स: 23412202, ईमेल: nbtedit@timesofindia.com, फैक्स: 23368917 पृष्ठों: 16+8। 23.08.2025 दिनांक के लिए। संपादक (नवभारत टाइम्स): राजेश्वरी सिंह। मुख्य कार्यालय: दिनांक वेब पृष्ठ: 1-16, वेब संपादक: विनोद के. मुख्य मुद्रक: ओमप्रकाश सिंह। चेन्नई: ए. वेंकटेश। बेंगलुरु: के. संपादक: दिनांक 8-9, कोलकाता: टिपिकल पब्लिशर्स। आवश्यक शुल्क: 20 अंक: नेपाल/श्रीलंका में रुपये 40 (अग्रिम) या समतुल्य। मुद्रित अंश, अंक 18, रुपये के अतिरिक्त लागू।

46 प्रतिशत देश की जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहे। हालांकि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या गांव में ही निवासक रही है, परंतु गांव में रहने वाले सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर नहीं हैं।

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

रोजगार के मामले में बदलता दृष्टिकोण

हाल की कुछ घटनाएं दर्शाती हैं कि कारपोरेट दुनिया के एक विशेषवर्ग ने शेयरधारकों के लिए अधिकतम मूल्य की खोज में कर्मचारियों की संख्या में कटौती किए जाने के रूप में एक नए और अजीब पैमाने की तलाश की है। सिलिकान वैली के दिग्गजों से लेकर भारत की आइटी कंपनियों तक, छंटनी की घोषणाएं गर्व के साथ की जाती हैं और शेयर बाजार एक तयशुदा उत्साह के साथ जोश में आकर उछाल दिखाता है। ऐसे में रोजगार के दृष्टिकोण से इस परिदृश्य को देखा जाना चाहिए, खासकर भारत के संदर्भ में इसके व्यापक निहितार्थों को भी समझा जाना चाहिए

बीते दिनों कारपोरेट दुनिया की कुछ कंपनियों ने अपने कार्यदक्षता को बढ़ाने और लाभप्रदता को अधिक करने के लिए कर्मचारियों की संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। यह कभी अंतिम और गंभीर कदम माना जाता था, अब रणनीतिक दूरदर्शिता का तमगा बन गया है। मगर इस तात्कालिक वित्तीय उछाल की चमक के पीछे, एक जटिल और चिंताजनक कहानी उभर रही है। क्या यह कटौती का जुनून बाकई लंबे समय तक चल सकता है, या हम एक गहरे, नापसंद इंसानी और संस्कृतिक नुकसान को जमा होते देख रहे हैं?

वस्तुतः आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी बदलावों के दौर में लागत कम करना तुरंत और ठोस लाभ देता है। निवेशकों के दबाव में जूझ रहे निदेशक, कम वेतन और मोटे मुनाफे के बीच सीधा रिश्ता देखकर राहत महसूस करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जो कम से कम मानव प्रयास के साथ अभूतपूर्व परिणाम देने का वादा करती है, एकदम सही बहाना बनती है। यह छंटनी को संकट का संकेत नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता का सबूत बनाती है। बाजार हमेशा अल्पकालिक नजरिया रखता है, इस कदम को उत्साह के साथ पुरस्कृत करता है, एक तात्कालिक कटौती को दीर्घकालिक रणनीति समझने की भूल करता है। लेकिन यह आसान गणित उस जटिल मानवीय पूंजी को नजरअंदाज करता है, जो वास्तविक और स्थायी मूल्य का आधार है।

भारत का मानवीय समीकरण : इस प्रवृत्ति की बारीकियां भारत में कहीं अधिक स्पष्ट हैं। हाल ही में बेंगलुरु से वाल स्ट्रीट जर्नल की एक कालपनिक खबर ने बताया कि वैश्विक तकनीकी छंटनी का असर भारत जैसे समाज में कई गुना बढ़ जाता है, जहां नौकरी केवल वेतन से कहीं अधिक मायने रखती है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां नौकरी बदलना आम है, भारत में एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि पूरे परिवार की भलाई का प्रतीक है। यह भाई-बहनों की शिक्षा, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को आधार देती है। जब कोई कंपनी अपने कार्यबल को "सही आकार" देने की बात करती है, तो वह अनजाने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुबंध तोड़ रही होती है। इसका सांस्कृतिक नुकसान भारी है: सामाजिक सम्मान की हानि, संस्थाओं में भरोसे का टूटना और एक व्यापक असुरक्षा की भावना, जो उपभोग और नवाचार को दबा देती है। हालांकि भारत के पारिवारिक ढांचा इस प्रभाव को बढ़ाते हैं, वहीं पश्चिमी देशों में भी नौकरी की असुरक्षा से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और उपभोक्ता खर्च में कमी देखी जाती है। एक विदेशी अखबार ने रेखांकित किया कि जहां पश्चिमी कंपनियां छंटनी को एक लेन-देन की घटना मानती हैं, भारत में इसे विश्वासघात के रूप में देखा जाता है, जो भविष्य की आकांक्षाओं के ताने-बाने को तोड़ देता है।

भारत का आइटी क्षेत्र, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास का आधार और लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है, इस "कटौती के जुनून" से खास तौर पर प्रभावित हुआ है। वर्ष 2023 में 50 लाख से अधिक पेशेवरों वाले इस क्षेत्र में छोटी-सी प्रतिशत कटौती भी लाखों लोगों की बेरोजगारी में बदल सकती है। खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों से आए उन लोगों के लिए जो तकनीकी केंद्रों में आए, ये नौकरियां सामाजिक उन्नति का रास्ता थीं, जो पूरे परिवार को बेहतर जीवन देती थीं।

"वैश्विक आर्थिक चुनौतियों" या "पुनर्गठन" के नाम पर हाल की छंटनी ने इस समूह की गहरी चोट पहुंचाई है। विश्लेषण यह भी है कि पश्चिमी देशों की तरह मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव में, नौकरी छिनने का असर हमारे देश में गंभीर होता है, जो परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल देता है। इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारों का कम खर्च छोटे व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करता है।

भरोसे का क्षरण : यह भरोसे का क्षरण सीधे कारपोरेट संस्कृति के केंद्र को प्रभावित करता है। कभारदी, जो कभी लंबी नौकरी का आधार थी, अब पुरानी बात लगती है। जब कर्मचारी अपने साथियों, खासकर लंबे समय तक सेवा देने वालों को छंटता के नाम पर अचानक बर्खास्त होते देखते हैं, तो एक डर फैल जाता है। बचे हुए कर्मचारी, जिन्हें "बचने वाले" कहा जाता है, अक्सर बढ़े हुए काम के बोझ, थकान और इस चिंता से जूझते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। उनकी प्रतिबद्धता कम होती है, अतिरिक्त प्रयास करने की इच्छा घटती है, और उनका ध्यान नवाचार से हटकर केवल जीवित रहने पर केंद्रित हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण, संस्थागत स्मृति, मौन ज्ञान और वर्षों में बने मूल्यवान नेटवर्क हर निकलने वाले कर्मचारी के साथ बाहर चले जाते हैं। इस बौद्धिक पूंजी को फिर से बनाना, जो अक्सर महंगी और समय लेने वाली भर्ती प्रक्रियाओं से होता है, छंटनी के शुरुआती लागत-लाभ विश्लेषण में शायद ही शामिल होता है।

इसके अलावा, कम कर्मचारियों और निरंतर लाभप्रदता के बीच मान गया संबंध अक्सर एक भ्रामक द्वंद्व है। हालांकि तात्कालिक लागत बचत स्पष्ट है, नवाचार, रचनात्मकता और ग्राहक अनुभव पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। लगातार तनाव में काम करने वाला कार्यबल प्रयोग करने, जोखिम उठाने या वह अतिरिक्त प्रयास करने की संभावना कम रखता है, जो बाजार में अग्रणी कंपनियों को अलग करता है। ग्राहक सेवा, जो अक्सर गहरी लागत कटौती का पहला शिकार होती है, प्रभावित होती है, जिससे ब्रांड की छवि खराब होती है और राजस्व कम होता है। सच्ची लाभप्रदता, एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में केवल लागत कम करने का परिणाम नहीं, बल्कि मूल्य की अधिकतम करने की प्रक्रिया है, जो एक सशक्त कार्यबल से जुड़ी होती है। कंपनियां इस बात पर प्रतिस्पर्धा करती हैं कि कौन अधिक कटौती कर सकता है, न कि कौन सबसे अधिक मूल्य सृजित कर सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण : औद्योगिक क्रांति के दौरान मशीनों के आगमन ने अक्सर कुशल हस्तशिल्प श्रमिकों को विस्थापित किया, जिससे व्यापक सामाजिक अशांति और शुरुआती श्रमिक आंदोलनों का जन्म हुआ। 20वीं सदी के मध्य में बिग्मीन में स्वचालन ने उत्पादकता बढ़ाई, लेकिन आटोमोटिव और इस्पात जैसे उद्योगों में नौकरी छिनने की चिंता भी पैदा की। 1980 के बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा कुछ इस तरह शुरू हुई जिसका लक्ष्य शेयरधारक मूल्य बढ़ाना था। इस दौर ने इस विचार को मजबूत किया कि कंपनियों की पहली जिम्मेदारी शेयरधारकों के प्रति है, कर्मचारियों के प्रति नहीं। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या कम करने की ओर जोर दिया गया, जो प्रैमासिक आय रिपोर्ट से कहीं आगे तक गूंजती है। एक कुशल उद्यम का असली मापदंड केवल लागत कम करने की उसकी क्षमता नहीं, बल्कि स्थायी मूल्य उत्पन्न करने की उसकी योग्यता है, जो मानव पूंजी के पोषण और सशक्तीकरण से जुड़ा है।

जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था एक जटिल भविष्य की ओर बढ़ रही है, कारपोरेट नेताओं को तात्कालिक स्प्रेडशीट से परे देखना होगा और यह पहचानना होगा कि डिस्पोजेबल श्रम पर आधारित समाज अंततः नाजुक है, जो किसी भी अल्पकालिक लाभ से कहीं भारी कीमत चुकाने के लिए बाध्य है। सवाल यह नहीं कि कोई कंपनी कितनी कमजोर हो सकती है, बल्कि यह कि मानव तत्व को व्यवस्थित रूप से कम करके वह कितनी मजबूत रह सकती है।

(डा. विकास सिंह)

दीर्घकालिक रणनीति को दी जाए प्राथमिकता

कारपोरेट द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने की समस्या से किस प्रकार निपटा जाए, इस बारे में भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कंपनियां कभी भी जानबूझकर इस तरह के उपाय या कदम नहीं उठाती हैं। फिर से कुछ हद तक यह आर्थिक चुनौतियों का चक्रीय जवाब है, मंदी के दौरान कारपोरेट की एक जानी-पहचानी प्रतिक्रिया। मंदी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या उपभोक्ता मांग में बदलाव जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के कारण छंटनी कभी-कभी अपरिहार्य होती है, कंपनियां अल्पकालिक जीवित रहने को प्राथमिकता देती हैं। फिर भी, मौजूदा दौर अलग लगता है, जिसमें एआइ की तकनीकी अनिवार्यता शामिल है। यह मानव श्रम के मूल्यांकन में एक बुनियादी बदलाव का संकेत देता है। निवेशकों का दबाव, जो शेयरों में तात्कालिक उछाल से बढ़ता है, इस व्यवहार को और मजबूत करता है। लेकिन इस बारे में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि अंतिम हिसाब में कर्मचारी संख्या में कटौती का मौजूदा कारपोरेट जुनून जो शेयरधारकों को तात्कालिक संतोष देता है, टिकाऊ विकास की नींव को कमजोर करने का जोखिम उठाता है। वर्ष 2023 के गैलप अध्ययन में पाया गया कि वार-बार छंटनी करने वाली कंपनियों में कर्मचारी जुड़ाव में 20 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कम उत्पादकता और नवाचार से जुड़ा था। उत्साहित "दक्षता" अक्सर गहरे संस्कृतिक नुकसान की कीमत पर आती है, जो कभारदी को कम करती है, नवाचार को दबाती है और एक व्यापक असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जिससे संस्थाओं में अविश्वास बढ़ा। परंतु यह समझना होगा कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच "सामाजिक अनुबंध" का क्षरण, जहां कभारदी का बदला नौकरी की सुरक्षा से मिलता था, एक दीर्घकालिक सामाजिक परिणाम रहा है। इससे काम के प्रति एक अधिक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है, जहां व्यक्ति अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देते हैं और अपने नियोक्ताओं की दीर्घकालिक सफलता में कम निवेश करते हैं, जिससे काम और समाज का ताना-बाना मौलिक रूप से बदल गया है।

फिर से

इंटर की बालिकाएं

चिड़ियों के चहकने से पहले ही मां उठ जाती थी और उठते ही काम करना शुरू कर देती थी। रात में लैंप की रोशनी में देर तक पढ़ने की वजह से आंख खुलने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन तब भी जबरदस्ती आंख मींचते हुए उठना पड़ता था, वरना कालेज के लिए देर हो जाती। जल्दी से उठकर हैंडपंप चलाकर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मार कर स्वयं को जगाना पड़ता था।

फिर उठते ही सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाकर, रसोई में झाड़ू लगाकर चूल्हे की राख उठाते और फिर चूल्हे को चिकनी मिट्टी से पोतकर साफ करके फिर बर्तन धुलते, नहाने के बाद दाल, भात, रोटी, तरकारी बनाकर फिर से हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनते, बैग की किताबें को टाइम टेबल के हिसाब से रखकर, रोटी के चार निवाले निगल कर, रोटी और सब्जी टिफिन में डालकर और फिर साइकिल साफ करते करते मां को रसोई की सारी जानकारी देते कि सारा भोजन बन गिया है दाल में तड़का लगना रह गया है, मुझे देर हो रही है मेरी सहेली प्रतीक्षा कर रही होगी तड़का आप लग लेना मैं जा रही हूं...

जल्दी से सहेली के घर पहुंचते। दोनों सखियां पगडंडियों पर साइकिल चलाकर पक्की सड़क को जोड़ने वाले तिराहे पर पहुंचते, वहां थोड़ी देर रुक कर बाकियों की प्रतीक्षा करते और फिर सखियों का झुंड साइकिल लेकर हंसते, बतियाते कालेज जाते तो लगता कि चिड़ियों का झुंड चहचहाते हुए बेफिक्री से चला जा रहा हो।

अक्सर किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम था। सखियों के बीच बैठकर टीवी सीरियल पर, नई फिल्म की स्टोरी, उसके गाने, हिरोइन के कपड़े, अपनी मैडम की सहिरयों की चर्चा हमारे बात करने का मुद्दा हुआ करती थी। तब हमारे पास पहुंचाइए मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन देर सारी बातें करने वाली ढेरों सखियां थीं।

आज इंटरनेट मीडिया पर हजारों फालोअर्स हैं, लेकिन दिल की बात करने के लिए लोगों के पास मित्र बहुत कम हैं। दिल की बातें अब मित्रों से नहीं होतीं, इंटरनेट मीडिया पर सेटएस के माध्यम से होती हैं। आज ढेरों सुविधाएं हैं, लेकिन मन का चाह सुकून नहीं है।

(संजीव कुमार की फेसबुक वाल से संपादित अंश, साभार)

पोस्ट

वह हास्यास्पद ही है कि चुनाव आयोग अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के मामले में राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग रहा है, लेकिन ऐसे ही आरोप लगाने वाले अनुराग ठाकुर से नहीं।

अशुतोष@ashutosh83B

चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से कई संदेश दूर किए, लेकिन उसे और सख्त रवैया अपनाना होगा कि हमारे संस्थानों की साख धूमिल करने एवं लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ कड़े कदम उठाए। केवल माफीनामे से काम नहीं चलेगा। बात तब बनेगी जब फर्जी खबरें फैलाने और लाखों लोगों को गुमराह करने वाले को अपनी करतूतों की कीमत चुकानी पड़ेगी।

अरविंद@aravind

देश में सड़कों पर ट्रैफिक जाम इसलिए नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कारें हैं, बल्कि इसलिए लगता है कि तमाम ड्राइवर यातायात नियमों का सही से पालन नहीं करते। नियमों को धता बताकर आगे बढ़ने का दांव ही जगह देरी का कारण बनता है।

जावेद अख्तर@Javedakhtarjadu

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ट्रंप-पुतिन मुलाकात के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के आसार दिख रहे हैं?

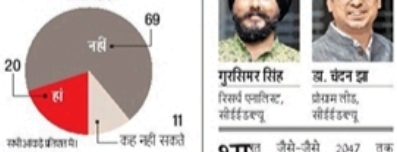

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना सही है कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दें या माफी मांगें?

परिणाम जागरण हाइपरलोकल संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कुत्ता पहुँचा कोर्ट में उसको चाहिए न्याय,
हाथी पहुँचा कोर्ट में उसको चाहिए न्याय।
उसको चाहिए न्याय कह रहे सब ज्ञानी अभी,
कहें कबूतर जल्द करो तरी अब 'जीओ'!
सिर्फ आम इंसान कोर्ट में जूते घुटरा,
पा जाते है न्याय यहाँ परहाथी-बुतरा!!

- अभिलाषा तिवारी

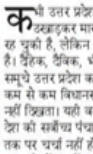

अजय शुक्ला
ajay.shukla@ltko.jagran.com

उत्तर प्रदेश डायरी

दैहिक, दैविक, भौतिक तापा...

कभी उत्तर प्रदेश विधानसभा माइक उखाड़कर मारपीट के लिए प्रसिद्ध रह चुकी है, लेकिन अब यहां 'समरांज' है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा... अब समूचे उत्तर प्रदेश का तो राम जानें, पर कम से कम विधानसभा में तो यह ताप नहीं दिखता। यही वजह है कि जहां देश की सर्वोच्च पंचायत में मौजूदा मुद्दों तक पर चर्चा नहीं हो पाती (व्यवधान कुछ भी हों) वहीं, प्रदेश विधानसभा में भविष्य के मुद्दों पर भी 24 घंटे की चर्चा हो जाती है। यह अलग बात है कि वे वर्तमान में ही उलझे रह जाते हैं।

विधानमंडल का मानसून सत्र 11 से 14 अगस्त तक चला। विधानसभा की कार्यवाही 32 घंटे से अधिक चली। इसमें भी 24 घंटे से अधिक समय 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश-2047' विजन डाक्यूमेंट को समर्पित रहा। सरकार को घेरने का हरसंभव मौका तलाशने वाले विपक्ष के 'अपेक्षित' विरोध के बीच दोनों सदनों में विधायी कार्य संपन्न हुए। विपक्ष की शिकायत रही कि बाढ़, खाद संकट, बेरोजगारी, फोरेंसिक में मकबरा बनाम मंदिर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई बदसलूकी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। वह भी तब जबकि सदन में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के अगले 22 साल के विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा के समय कर्मचारी विधान भवन में बारिश के पानी को रात भर बाहर निकालते रहे।

विधायी कार्यों में भी कोई अड़चन नहीं आई। पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2025, निजी विश्वविद्यालयों के नियमन के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, जीएसटी नियमों में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित हुआ। सत्र में छह प्रमुख विधेयक पेश किए गए, जिनमें श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 भी शामिल रहा। वैसे कभी नकारात्मक वजहों से जिस उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की चर्चा होती रही है, उसका सत्र अन्य विधानमंडलों के लिए अनुकरणीय रहा।

विधानसभा परिसर में फूड पाल। फाइल

सलीम तुझे मारने नहीं देगा : फिल्म 'मुगल-ए-आजम' का एक संवाद है- 'सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे अनारकली।' यह गति उन आठ विधायकों की है जो चुनकर तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आए थे, लेकिन जाति, जुगाड़ और जिद्द के कारण भाजपा का पाला छूकर बार्डर पर खड़े हैं। बीते सत्र राज्यसभा चुनाव में सपा के आठ विधायकों ने भाजपा का पाला छू लिया था। इनमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश प्रताप सिंह, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज पांडेय, अमेठी से पूर्व मंत्री गयत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी, अंबेडकर नगर की जलालपुर से राकेश पांडेय, कानपुर नगर की कल्याणपुर से विनोद चतुर्वेदी और कानपुर देहात से आशुतोष मौर्य के साथ कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल शामिल रहीं। सपा ने फाउल खेलने के बावजूद इन्हें कुनबे से बाहर नहीं किया था। कारण, एक तो दलबदलुओं की विधायकी को प्रिरंकु बनाकर रखने की परंपरा। यानी, बाहर कर दिया तो स्वतंत्र अन्यथा विधायकी जाने के डर से अधर में लटके रहने की मजबूरी। दूसरे, मन बदलने का इंतजार।

जून में अखिलेश ने फैसला लिया कि कुछ विधायकों को स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि अब एक तो इनकी वापसी की संभावना क्षीण थी और दूसरे फिल्मी स्टाइल में इनको यह सबक देना था कि 'जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी।' यानी, देखते हैं कि भाजपा तुम में से किसको बनाती है मंत्री। जिन्हें स्वतंत्र किया गया उनमें अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडेय थे। 'सिंह' बंधुओं को तो इसलिए आजाद किया गया, क्योंकि जातीय कारणों से उनका झुकाव सत्तापक्ष की ओर था। पांडेय को इसलिए, क्योंकि वह मंत्री बनने के लिए डबल क्रास कर रहे थे। निष्कासन का फैसला खासतौर पर मनोज पांडेय के लिए ही था, इस चुनौती के साथ कि देखें मंत्री बनते हो कि नहीं। शेष ब्राह्मणों और पिछड़ों को इसलिए छोड़ दिया गया कि इनका मन बदल सकता है और आगे पंचायत चुनाव में ताकत भी दिखानी है।

पूजा पाल विधानसभा सत्र में बिना वजह शिकार बन गईं। खता बस इतनी थी कि विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान पूजा ने माफिया अतीक अहमद की 'मिट्टी में मिलाने' के लिए मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। पूजा उन राजू पाल की पत्नी हैं जो अतीक और उसके छोटे भाई अशरफ की गुंडई का शिकार हुए और जान से हाथ धो बैठे। यही तारीफ अखिलेश को साइकिल के पोडियम रूपी टायर में पंक्चर सरीखे जान पड़ी और उन्हें बाहर कर दिया। मामला अब बराबरी पर है। सिवासत की चार अनारकली (अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडेय और पूजा पाल) भाजपा के खेमे में हैं और चार (महाराजी देवी, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडेय और आशुतोष मौर्य) सपा के पाले में। वर्ष 2027 के पहले अब किस अनारकली को क्या मिलता है, यह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा पूजा पाल की बनी हुई है।

मंथन

गुरसिमर सिंह
रिसर्च एनालिस्ट, सीईईडब्ल्यू

डा. चंदन दुआ
प्रोग्राम लीड, सीईईडब्ल्यू

जलवायु अनुकूल खेती पर जोर

खेती-किसानी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' की पहल शुरू की गई है। परंतु इसकी सफलता के लिए दीर्घकालिक प्रारूप भी तैयार करना होगा

भारत जैसे-जैसे 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, इसके विकास का रास्ता समावेशी, जलवायु संकटों को सहने में सक्षम (क्लाइमेट-रेजिलिएंट) और विभिन्न क्षेत्रों के समुदायों की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। यह बात कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक जरूरी हो जाती है, जो देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है और जलवायु संकट के लिए बहुत ही सुभेद्य है। कृषि मंत्रालय ने इस साल 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' भारतीय कृषि में जलवायु संकट को सहने की क्षमता बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है, जिसका फलदा चरण जून में पूरा हो चुका है।

यह प्रयास ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब भारतीय कृषि कई पुरानी चुनौतियों का सामना कर रही है। राज्य-स्तरीय जलवायु कार्रवाई की क्षमता पर किए गए कार्टसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान नीति निर्माण में जिनको लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, अक्सर उन्हीं समुदायों की स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी कर दी जाती है। नतीजा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की खपत करने वाली फसलों के प्रोत्साहन और उर्वरकों के आत्यधिक उपयोग से मिट्टी की खराब सेहत के रूप में सामने आता है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान इन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है, जिसके तहत आईसीएआर और कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों को प्रत्येक फसली सीजन से पहले गांवों का दौरा करने, प्रयोगशाला से खेत के बीच के अंतर को दूर करने का आदेश दिया गया है। यह प्रत्यक्ष जुड़ाव स्थानीय चुनौतियों को बेहतर समझ बनने, नवाचारों की पहचान करने और क्षेत्र-आधारित वैज्ञानिक सबूत को जुटाने में सक्षम बनाता है, जो जनकेंद्रित नीति निर्माण का रास्ता तैयार करता है। इसके लिए इस अभियान को तीन प्रमुख कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है।

सबसे पहले, नीतिगत समंजस्य लाने के लिए क्लाइमेट-रेजिलिएंट कृषि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। भले ही वर्तमान परिभाषाओं में खाद्य सुरक्षा, सामग्रता, उपज में सुधार और जलवायु अनुकूलन व शमन शामिल हैं, लेकिन सीईईडब्ल्यू एक अध्ययन के अनुसार क्लाइमेट-रेजिलिएंट कृषि को आगे बढ़ाने वाले भारत के लिए प्रासंगिक तीन महत्वपूर्ण पहलू गायब हैं: सुभेद्य किसानों के लिए आर्थिक व जलवायु संकट को सहने की क्षमता (लचीलापन) तथा, उत्सर्जन घटाने जैसे दीर्घकालिक लाभ देने वाले जलवायु अनुकूलन उपायों को अपनाना और केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की जगह पर पोषण सुरक्षा के लिए विविध आहारों तक पहुंच को सुनिश्चित करने पर ध्यान देना।

दूसरा, समावेशी प्रशासन को बढ़ाने के लिए जमीनी संगठनों को स्पष्ट भूमिकाएं सौंपना। विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान ने पहले ही विज्ञानियों और अधिकारियों को एक साझा मंच बैठाया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों के लिए एक अधिक सक्रिय भूमिका किसानों के बीच फसल विविधीकरण और क्लाइमेट-रेजिलिएंट पद्धतियों जैसे प्राथमिकताओं को रफ्तार दे सकती है।

तीसरा, राज्य-स्तर पर स्पष्ट परिणाम निर्धारित करने के लिए विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाना। सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी से नीतियों का प्रभाव कमजोर होता है। उदाहरण के लिए, सिंचाई विभाग की बिजली सब्सिडी से कृषि उपज में सुधार हो सकता है, लेकिन भूजल में गिरावट आ सकती है, जिससे जल संरक्षण के लक्ष्य कमजोर हो सकते हैं। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान में प्रत्येक राज्य के जल, ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य विभागों को शामिल करना चाहिए, जिससे वे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण या जलवायु अनुकूलन जैसे परिणामों को आपस में मिलकर तय कर सकें। ग्राम-स्तरीय जानकारी इन लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हो सकती है। नीतिगत समंजस्य लाने की एक चेकलिस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि नई या मौजूदा नीतियां राज्य के परिणामों के अनुरूप हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, इसमें यह सवाल हो सकता है कि राज्य के लक्ष्यों पर नीतियों के प्रभाव का आकलन किया गया है या नहीं या क्या यह अन्य क्षेत्रीय उद्देश्यों को कमजोर करती है।

खेती में जलवायु संकट से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। फाइल

जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, तब हमें यह समझना होगा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर लगभग 46 प्रतिशत आबादी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान गहरे संकट, बेहतर समन्वय और स्थानीय रणनीतियों के माध्यम से कृषि को जलवायु संकटों का सामना करने में सक्षम बनाने का अवसर देता है। लेकिन इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि केवल एक अभियान बनाने से आगे बढ़कर यह एक दीर्घकालिक प्रशासन रूपरेखा बन जाए।

****

दैनिक जागरण
सफलता का आधार है इच्छाशक्ति

सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे

यह अच्छा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगा रहे राहुल गांधी के आरोपों का न केवल विदुयार जवाब दिया, बल्कि उन्हें बेनकाब करते हुए यह भी कहा कि वे या तो अपने निराधार आरोपों के संदर्भ में शपथ पत्र दें या सात दिनों के अंदर देश से माफी मांगें। राहुल गांधी को ऐसी चेतावनी देना आवश्यक था, क्योंकि वे अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा पर जानबूझकर चोट करने में लगे हुए हैं। इसके पहले वे और कुछ अन्य विपक्षी नेता ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाया करते थे। जब ऐसे आरोप निराधार साबित हुए तो वे वोट चोरी की नई कहानी लेकर सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कुछ कहा, उसका यही अर्थ था कि यह कहानी फर्जी है। उन्होंने हाउस नंबर जीरो वाले मतदाताओं के मामले में राहुल और उनके जैसे अन्य नेताओं को न केवल आईना दिखाया, बल्कि वस्तुस्थिति से भी अवगत कराया। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों में कथित धांधली के राहुल के आरोपों की पोल खोली। इसके साथ ही उनकी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि यह पहली बार नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ऐसा 2003 में भी हुआ था।

इसमें संदेह है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों पर गौर करेंगे और अपना रवैया बदलेंगे। इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि गत दिवस ही राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कांफ्रेंस से पहले बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनकी मानें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई थी। अच्छा होता कि राहुल अथवा उनके साथी-सहयोगी यह समझ लें कि यदि ऐसा हुआ था तो कांग्रेस 99 सीटें कैसे पा गई और भाजपा 240 पर क्यों सिमट गई? वास्तव में राहुल गांधी का इरादा तथाकथित वोट चोरी के मामले को उजागर करना नहीं, बल्कि चुनाव आयोग एवं भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करके अविश्वसनीय बनाना है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः वह जान गए हैं कि चुनावी मैदान में जीत हासिल करना उनके बस की बात नहीं। जो भी हो, यह आवश्यक हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करे। उसे हस्तक्षेप केवल इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इस मामले की सुनवाई कर रहा है, बल्कि इसलिए भी करना चाहिए कि एक संवैधानिक चुनाव से जड़ें खोदी जा रही हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा होते हुए कैसे देख सकता है—और वह भी तब जब वह बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को सही ठहरा चुका है।

सुलझती नहीं समस्या

सरकारी काम हो और कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसकी कल्पना करना कठिन है। उत्तर प्रदेश के मऊ में आपूर्ति विभाग के चक्कर लगाते-लगाते एक वरिष्ठ नागरिक राधेश्याम का धीरज चुक गया। वह विषधर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनका तरीका गलत था, लेकिन क्रोध अनुचित नहीं था। उनका राशन कार्ड पिछले साल ई-केवाईसी के नाम पर निरस्त हो गया था। वह महीनों कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन समस्या अनसुलझी रही। दो मत नहीं कि राशन कार्ड कमजोर वर्ग के लिए बड़ी आवश्यकता है। प्रदेश में लगभग 15 करोड़ लोग राशन कार्ड के माध्यम से राशन पर आश्रित हैं। इनमें 40.73 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक शामिल हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि राधेश्याम की तरह बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा या कर रहे होंगे। पात्रों को ही योजनाओं का लाभ मिले, ई-केवाईसी जैसी व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन इसके लिए किसी वरिष्ठ नागरिक को पीड़ा झेलनी पड़े, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रशासन की संवेदनहीनता और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। जन समस्याओं को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री गंभीर रहते हैं। प्रतिदिन लोगों की समस्या सुनते हैं और समाधान भी कराते हैं, लेकिन अधिकारीगण विपरीत तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, जो अन्य के लिए सीख साबित हो।

> किसी वरिष्ठ नागरिक को पीड़ा झेलनी पड़े, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता

अपनी ही बिसात पर मात खा गए ट्रंप

शिवकांत शर्मा

जब तक यूक्रेन युद्ध को लेकर वार्ताओं का दौर जारी रहेगा तब तक रूसी तेल खरीद के मामले में भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ का बोझ नहीं पड़ना चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर वार्ता से नहीं निकला कोई ठोस परिणाम • एएफपी

इस बात पर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ हो कि राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर वार्ता से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि 'पुतिन ने युद्धविराम से इन्कार किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे' की धमकी देकर शिखर वार्ता में जाने वाले ट्रंप तीन घंटे चली वार्ता से यह कहते हुए कैसे निकले कि वे 'अस्थायी युद्धविराम की जगह स्थायी शांति समझौते को प्राथमिकता देंगे।' उनके बदले सुरों से तो यही संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति पुतिन अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखकर उनकी राय बदलने में कामयाब रहे। इसे देखकर यही लगता है स्वनामधन्य सौदा-निपुण ट्रंप साहब की कोई चाल कारगर नहीं सिद्ध हो पाई।

शिखर वार्ता के बाद पुतिन ने कहा कि हम ईमानदारी से चाहते हैं कि यूक्रेन का संघर्ष समाप्त हो, पर इसके स्थायी और दीर्घकालिक समाधान के लिए हमें उसके बुनियादी कारणों को दूर करना होगा। पुतिन शुरू से ही यूक्रेन को नाटो में शामिल करने और यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार लाने के कथित षड्यंत्र को इस संघर्ष का बुनियादी कारण मानते रहे हैं। यही दलील देकर उन्होंने 2014 में क्रीमिया प्राबद्दीप पर कब्जा किया था और साढ़े तीन साल पहले यूक्रेन पर हमला शुरू किया। ऐसे में ट्रंप जिन बातों पर सहमति का इशारा कर रहे हैं, उनमें पहली तो यही हो सकती है कि ट्रंप की तरह पुतिन भी अब संघर्ष का समाधान चाहते हैं। दूसरी सहमति यूक्रेन को नाटो में शामिल न करना हो सकती है। तीसरी, दोनों का यह मानना कि बाइडन की जगह यदि ट्रंप राष्ट्रपति होते तो शायद लड़ाई छिड़ने की नौबत नहीं आती। इसके अलावा यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि दोनों ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को पसंद नहीं करते।

ट्रंप ने जिन अड़चनों का संकेत दिया है, उनमें सबसे प्रमुख यूक्रेन के वे चार पूर्वी प्रांत हैं जिनके अधिकांश भाग रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं। ट्रंप कई बार इशारा कर चुके हैं कि यदि यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों की पूरी जमीन रूस को सौंप दे और क्रीमिया को भूल जाए तो बदले में रूस खारसोन और जकरोजिया प्रांतों की जीती हुई जमीन लौटा सकता है। शायद इसी मुद्दे पर आगे बात करने के लिए जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया गया है। हालांकि जेलेंस्की सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि वे जमीन देकर आक्रांता से शांति खरीदने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और वह भी रूस जैसे आक्रांता से जो शांति की जुबान देकर कभी भी मुकर सकता है। जेलेंस्की तैयार भी हो जाएं तो उनकी संसद तैयार नहीं होगी। पुतिन भी यह जानते हैं। शायद इसीलिए असंभव शर्तें रख रहे हैं। वैसे भी रूस को जीती हुई जमीन देकर शांति का सौदा करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन होगा और पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यूक्रेन और रूस दोनों की असुरक्षा की भावना दूर करने का है। नाटो और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के बिना यूक्रेन के अस्तित्व को खतरा है और इनकी यूक्रेन में उपस्थिति को रूस खतरा मानता है।

ट्रंप को लगता था कि तालियां बजाकर स्वागत-सत्कार करके वे पुतिन को किसी नाटकीय शांति समझौते के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन पुतिन ने सिद्ध कर दिया कि वे कूटनीतिक शतरंज के माहिर हैं। युद्धविराम भी नहीं किया और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय वार्ताओं की बात मानकर उन आर्थिक प्रतिबंधों को कुछ समय के लिए टलवा लिया, जिनकी ट्रंप धमकी दे रहे थे। वार्ता के बाद एक एंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में वे दो-तीन हफ्ते बाद फैसला लेंगे। इसलिए जब तक यूक्रेन वार्ताओं का सिलसिला जारी रहता है तब तक भारत पर भी वह 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगना चाहिए जो रूस से तेल खरीदने के लिए लगना था। हालांकि ट्रंप के बारे में कोई भी अनुमान लगना संभव नहीं है। उसी चैनल को वार्ता से पहले दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस एक ऐसा ग्राहक खो चुका है जो उसका 40 प्रतिशत तेल खरीद रहा था। वे भारत की तरफ इशारा करके यह दावा कर रहे थे कि टैरिफ से बचने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत ने यदि ऐसा किया भी है तो उसका कारण यह भी तो हो सकता है कि बाजार में अब तेल की कीमतें उन्हीं दरों पर आ गई हैं, जिन रियायती दरों पर रूस से तेल मिल रहा था।

ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के अनुसार उनकी भारत से नाराजगी की असली वजह दरअसल रूसी तेल या हथियार खरीदना नहीं है। टेलीफोन पर आधे घंटे की वह बातचीत है, जो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कनाडा के जी-7 शिखर के बाद और ट्रंप के जनरल मुनीर के साथ लंच से एक दिन पहले हुई थी। इसी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को याद दिलाया था कि न तो आपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी और मोदी की कोई बातचीत हुई और न भारत द्विपक्षीय मामलों में किसी की मध्यस्थता स्वीकार करता है। ट्रंप तभी से बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान साल की शुरुआत से ही उन्हें साधने में लगा हुआ है।

कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप भारत और रूस के बीच दरार डालने और दबाव बढ़ाकर बेहतर व्यापार सौदा पटाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम निकलते ही बदल सकते हैं, लेकिन अमेरिका के पूर्व राजनयिकों और समीक्षकों की राय है कि ट्रंप तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए पांच सरकारों की 30 वर्षों की मेहनत से तैयार हुई चीन की काट को ठप्प पर लगा रहे हैं। आर्थिक और सामरिक नुकसान भारत को भी होगा, पर आशा है कि भारत इस आपदा का प्रयोग प्रधानमंत्री के शब्दों में अपनी लकीर बढ़ाने में कर सकता है और यूरोप, चीन, रूस, ब्रिक्स देशों और पूर्वी एशिया में अपना व्यापार फैला सकता है। अमेरिका के साथ सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना भी जरूरी होगा, लेकिन हेनरी किसिंजर का यह प्रसिद्ध कथन याद रखते हुए कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, पर दोस्ती कहीं ज्यादा घातक हो सकती है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

किसानों के हित में तनकर खड़ा भारत

केसी त्यागी

अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पादों के लिए रियायत चाहता है, पर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह संभव नहीं

लाल किले से किसान हित की बात करते पीएम। पीटी

अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत की अनिश्चितता के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह स्पष्ट किया कि वह किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा में ढाल की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत मांग रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनाल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ-साथ अमेरिकी डेरी उत्पादों को भारत में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के आदेश के बाद पीएम मोदी का यह वक्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि ट्रंप का यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो जाएगी।

अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार चाहता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह डेरी क्षेत्र और जीएम सोयाबीन और मक्का के लिए अपना बाजार नहीं खोलेगा। अमेरिका में पशु आहार का उपयोग डेरी क्षेत्र में किया जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने पहले के किसी भी व्यापार समझौते में कभी भी शूल्क की कोई रियायत नहीं दी है। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा मवेशियों को पशु उत्पाद खिलाने की प्रथा को लेकर भी चिंताएं हैं, जो स्थानीय मानदंडों और सुरक्षा संबंधी धारणाओं का उल्लंघन करती हैं। डेरी क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतिबंधित मांस पदार्थों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख अपनाने के कारण कृषि और देश के स्वाभिमान से जुड़े प्रश्नों को दरकिनार कर किसी समझौते की संभावना मुश्किल है। अमेरिका का आग्रह चीन को अपने निर्यात में गिरावट को लेकर उसकी चिंता से उपजा है। अमेरिका के सोयाबीन निर्यात में चीन का लगभग 55 प्रतिशत और मक्का निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका भारत से संपर्क करके अपने खरीदार आधार का विस्तार करना चाहता है। कृषि व्यापार में भारत का अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 6.25 अरब डालर रहा, जो 2023-24 में 5.52 अरब डालर था। वहीं कैलेंडर वर्ष 2023 में अमेरिका का भारत को निर्यात 37.3 करोड़ डालर था। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.51 अरब डालर था, जबकि अमेरिका से आयात कुल 45.69 अरब डालर था।

आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां वह एक छोर से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था से मुक्ति मिल सके। भारत के लिए कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए राहत सुनिश्चित करना एक प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। इसी बीच पैकेज के हिस्से के रूप में जीएम सोयाबीन और मक्का के निर्यात को शामिल करने के अमेरिका के आग्रह ने बातों पर लंबी छाया डाल दी है। अमेरिका से व्यापार वार्ता में जीएम फसलों भी एक सीमा रेखा बनी हुई है। भारत ने वैश्विक बाजार में एक गैर-जीएम उत्पादक के रूप में विशेष रूप से सोया, खली निर्यात में एक विशिष्ट स्थान बनाया है, जहां खरीदार सक्रिय रूप से प्राकृतिक किस्मों की तलाश करते हैं। भारत में मक्का से एथेनाल कम मात्रा में बनता है और अधिकतम मानव आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। जब पंजाब के लोग नशा विरोधी आंदोलन में पूरी तरह डूबे हुए हैं, तब जीएम के जरिए पंजाब की मिट्टी, पानी और हवा को और जहरीला बनाने की कोशिश बेहद निंदनीय है। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने इसे मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है।

भारत में अभी तक केवल जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की ही व्यावसायिक खेती हो रही है। 2010 में बीटी बैंगन को भी मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू हुई थी, पर नौ राज्य सरकारों, कई पर्यावरण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और किसानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके विरोध में आ गए हैं। विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए हैं। अमेरिका में एक प्रतिशत भू-भाग में जीएम मक्का की खेती की गई, जिसने 50 प्रतिशत गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी जमीन पर धान एवं मक्के की खेती की, मगर पांच-छह वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद वहां से जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी। इसे देखते हुए भारत का अपने किसानों के हित में अमेरिका के सामने सख्त रुख अपनाना समय की मांग है।

(लेखक पूर्व सांसद हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सम्मान और अपमान

सम्मान और अपमान हमारे जीवन की गहराई से प्रभावित करते हैं। जब कोई कठोर वचन बोलता है, तो उसका आघात मन को प्रभावित करता है, तब इसे अपमान कहते हैं। यह आघात हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और हमें दुखी बनाता है। जब किसी के द्वारा मानमर्दन किया जाता है तो प्रायः हृदय में उस व्यक्ति के प्रति विचार और भाव प्रदूषित हो जाते हैं। जब कोई सम्मान करता है, तब उसके प्रति हमारा चिंतन संवेदनात्मक और सकारात्मक हो जाता है और मनमयूर झूम उठता है। दूसरे को सम्मानित करने से वस्तुतः हम अपना ही सम्मान करते हैं, जैसे जब कोई किसी को इत्र-चंदनादि लगाता है, तो उसका भी हाथ सुगंधित हो जाता है। दूसरों को सम्मान देने से उनके हृदय में स्नेह-प्रेम के सुगंधित पुष्प खिल उठते हैं।

कठोर शब्द खंजर से भी तीक्ष्ण होते हैं और हृदय में गहरा घाव कर देते हैं। हमारे जीवन में शब्दों का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों भावों को समुत्पन्न करता है। सुसंग से वंचित प्रायः जो दूसरों पर कटु व्यंग्यबाण चलाते हैं, वे परोक्ष में अपने अंहकार का परिचय देते हैं, किंतु जो 'वासुदेव सर्वम्' इस शाश्वत तथ्य को सहज मन, वचन और कर्म में धारण करते हैं, वह सबका समुचित सम्मान करते हैं और यदि कोई अनुचित आचरण होता है, तो उसे नीतिपूर्वक समझा देते हैं, जैसे किसी के मुख पर कालिख लगी हो तो उससे नहीं कहते हैं, बल्कि उसे दर्पण के सम्मुख खड़ा कर देते हैं, जिससे वह स्वयं सचेत होकर उसे मिटा देता है।

हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए और दूसरों के साथ संवाद करते समय हमें अपनी भावना को नियंत्रित करना चाहिए। जानबूझकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम स्वयं अपने ही सम्मान को खो बैठेंगे। सम्मान करने से जीवन सुखमय और परस्पर संवेदना दे युक्त हो जाता है।

आचार्य नारायण दास

डे-केयर में बच्चों की सुरक्षा

सुनीता मिश्रा

कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को डे-केयर में इस भरोसे के साथ छोड़ते हैं कि वहां उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी

हाल में आई नोएडा के एक डे-केयर की घटना ने हर नौकरीपेशा माता-पिता को हरा दिया है। यहां 15 महीने की बच्ची के साथ घरेलू सहायिका ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजकल कामकाजी माता-पिता के लिए बच्चों की परवरिश एक चुनौती बन गई है। अधिकतर अभिभावकों को परिवार के अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति में अपने बच्चों की मजबूरी में डे-केयर, क्रेच या फिर घर में घरेलू सहायिका के भरोसे छोड़ना पड़ता है। कामकाजी माता-पिता अपने बच्चों को डे-केयर में इस भरोसे के साथ छोड़ते हैं कि वहां उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, उन्हें प्यार से संभाला जाएगा। वहां उनके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए वे डे-केयर संचालक की मोटी फीस भी देते हैं। छोटे बच्चे अपने परिवार और अपनों के बीच खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में डे-केयर संचालक और वहां काम करने वाले स्टाफ को बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी भावनाओं को ठीक से समझना चाहिए। अगर उनकी उपेक्षा की जाती है या उनकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती है, तो वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। डे-केयर वालों को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि नौकरीपेशा माता-पिता के कारण ही उन्हें रोजगार मिल रहा है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहे हैं।

ध्यान दें कि डे-केयर बच्चों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। यदि डे-केयर अच्छा है, तो यह बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए डे-केयर सफ-सुथरा होना चाहिए और वहां बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। अनुभवी और प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, जो बच्चों की देखभाल के साथ-साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दे सके। डे-केयर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, जिसके हर पल के फुटेज माता-पिता को जरूर मिलने चाहिए। सुरक्षा गार्ड और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए।

बच्चों को डे-केयर से लाने के बाद उनसे सवाल पूछना हर माता-पिता का दायित्व है। यह उन्हें सुरक्षित और खुश रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहा? क्या किसी बात ने आपको परेशान किया? क्या आप खुश थे? इस तरह के सवाल बच्चों की मनोदशा को समझने में मदद करेंगे। बच्चों के हावभाव और व्यवहार पर भी गौर करें। वहीं, जो बच्चे डे-केयर में गुजारे वक्त को बयां नहीं कर सकते माता-पिता उनके शरीर को ठीक से पढ़ाल करते रहें, देखें उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ताकि फिर कभी नोएडा जैसी घटना सामने न आ सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

संकल्प, संकट और संभावना

'प्रधानमंत्री के संकल्प' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में यह तथ्य रेखांकित हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्य की नीतिगत दिशा का संकेतक है। यह भाषण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का खाका प्रस्तुत करता है। एक आश्वस्त करें तो भाषण विचारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि चुनौतियों का मानचित्र है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की राह पर बल दिया, किंतु वास्तविकता यह है कि बिना शिक्षा सुधार, शोध विस्तार और नवाचार प्रोत्साहन के आत्मनिर्भरता अधूरी ही रहेगी। विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार का समन्वय ही वह बिंदु है, जो संकल्प को धरातल पर ला सकता है। यह समझना होगा कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक की स्वतंत्रता भी है। सुरक्षा और विदेश नीति की दृष्टि से यह भाषण सामरिक संतुलन पर केंद्रित दिखा, परंतु अमेरिका जैसे मित्र देशों से सहयोग लेते समय भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्भर निर्णय क्षमता की रक्षा एक बड़ी चुनौती है। यही वह मोड़ है जहां मित्रता और स्वाभिमान का संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है। आर्थिक सुधारों, जीएसटी पारदर्शिता और कर-प्रशासन सुधार का उल्लेख सकारात्मक है, परंतु बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट, ग्रामीण विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि विकास का सही अर्थ तभी सिद्ध होगा, जब गांव और शहर दोनों समृद्ध हों। अतः प्रधानमंत्री के 'संकल्प' प्रेरणादायक हैं, पर इनकी सफलता घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस नीतिगत क्रियान्वयन, न्यायिक पारदर्शिता और समावेशी विकास पर निर्भर करेगी।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा

बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। अच्छी बात है वोट पर चोट होती है, तो उसके प्रति मतदाताओं को सचेत करना नेताओं और उनकी पार्टियों का फर्ज होता है। पर चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट का बारीकी से पुनरीक्षण कर रहा है, आखिर को कितना गलत है। अगर फर्जी, अनुपस्थित और मृत मतदाताओं को आयोग निकालकर सही सूची तैयार कर रहा है तो इसमें हर्ज कैसा? क्या मतदान की पारदर्शिता के लिए यह कार्य ठीक नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के पास वोटर्स तक पहुंचने के लिए कोई ठोस मुद्दे ही नहीं बचे हैं इसलिए वोटर लिस्ट का ही मुद्दा उछाल रहे हैं? वोट अधिकार यात्रा के जरिए वे अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। क्या बढ़ते अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं से अत्याचार आदि मुद्दे गौण हो गए हैं। चुनाव करवाना, सही करवाना, मतदान में पारदर्शिता लाना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होना आदि ऐसी बातें हैं, जिन्हें चुनाव पूर्व दूर करने के प्रयास चुनाव आयोग को करने ही हैं। वैसे भी मतदान का अधिकार तो सबको है ही। अधिकार से वंचित तो मतदाता तब ही होता है, जब उसका वोट कोई और डाल जाता है। आयोग उसी को ही तो दूर करने के लिए मतदाता सूची को पुनरीक्षित कर रहा है। क्या फर्जी, अनुपस्थित और मृत लोगों के नाम नहीं हटाना चाहिए? आखिर इनके नाम हटा देने से कौन मतदाताओं का मताधिकार छिन रहा है। अगर विपक्ष के पास ऐसी मजबूत व्यवस्था हो कि वो ऐसे मतदाताओं की सूची पेश करे, चुनाव आयोग को जिनके नाम जुड़े या जोड़े नहीं गए हैं, तो मय प्रमाण के वो आयोग को प्रस्तुत करे। यदि वे नहीं जोड़ते हैं, तब मताधिकार से वंचित की बात पुख्ता हो सकती है और उसके लिए संघर्ष किया जा सकता है और तभी विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा सार्थक भी हो सकती है और उसे जनसमर्थन भी मिल सकता है। जनसमर्थन पाने के लिए पूरे देश में फर्जी, अनुपस्थित और मृत मतदाताओं की सूची से हटाने की बात/मुद्दे को लेकर बिहार ही नहीं, पूरे देश में वोट अधिकार यात्रा निकाली जाती तो कुछ और बात होती। क्योंकि केवल बिहार में ही सूची में गड़बड़ियां नहीं हैं, पूरे देश में मतदाता सूची में करोड़ों गलत नाम हट सकते हैं।

शुभकरण, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43566300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****